● वर्ष-4
● अंक-66
रायपुर, शुक्रवार
25 अक्टूबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» जयपुर में अब तक ये एडवेंचर ....

ब्रिक्स के मंच से जयशंकर की हुंकार

क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का हो सम्मान

आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं: विदेश मंत्री

कजान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन में कहा कि संघर्षों और तनाव से प्रभावी तरीके से निपटना आज के समय की विशेष जरूरत है। उन्होंने कहा कि संवाद और कूटनीति से विवादों और मतभेदों का समाधान निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बार सहमति हो जाए तो ईमानदारी से उसका पालन होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कानून का बिना किसी अपवाद के पालन होना चाहिए। विदेश मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला रुख होना चाहिए। एस जयशंकर ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष और फैलने को लेकर व्यापक चिंताएं हैं। उन्होंने कहा कि हम कठिन परिस्थितियों में मिल रहे हैं, विश्व को दीर्घकालिक चुनौतियों पर नए सिरे से सोचने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अतीत की कई असमानताएँ भी जारी हैं। वास्तव में, उन्होंने नए रूप और अभिव्यक्तियाँ ग्रहण की हैं। हम इसे विकासात्मक संसाधनों और आधुनिक तकनीक और दक्षताओं तक पहुँच में देखते हैं। हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि वैश्वीकरण के लाभ बहुत असमान रहे हैं। इन सबके अलावा, कोविड महामारी और कई संघर्षों ने वैश्विक दक्षिण द्वारा वहन किए जाने वाले बोझ को और बढ़ा दिया है।

विदेश मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, खाद्य और ईंधन सुरक्षा की चिंताएँ विशेष रूप से तीव्र हैं। भविष्य के शिखर सम्मेलन ने रेखांकित किया कि दुनिया एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी पीछे रह जाने के वास्तविक खतरे में है। उन्होंने सवाल किया कि हम इस विरोधाभास को कैसे सुलझाएँगे? और यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवर्तन का लाभ उन लोगों तक पहुँचे जो वर्तमान में पीछे रह गए हैं? हम एक अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था कैसे बना सकते हैं?

जयशंकर ने कहा कि सबसे पहले, स्वतंत्र प्रकृति के प्लेटफ़ॉर्म को मज़बूत और विस्तारित करके। और विभिन्न डोमेन में विकल्पों को व्यापक बनाकर और उन पर अनुचित निर्भरता को कम करके जिनका लाभ उठाया जा सकता है। यह वास्तव में वह जगह है जहाँ ब्रिक्स वैश्विक दक्षिण के लिए बदलाव ला सकता है। दूसरा, स्थापित संस्थाओं और तंत्रों में सुधार करके, विशेष रूप से स्थायी और अस्थायी श्रेणियों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद।

कोविड का अनुभव आश्यकता की तीखी याद दिलाला: जयशंकर

तीसरा, अधिक उत्पादन केंद्र बनाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था का लोकतंत्रीकरण करना। कोविड का अनुभव अधिक लचीली, निरर्थक और छोटी आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता की तीखी याद दिलाता है। आवश्यक आवश्यकताओं के लिए, प्रत्येक क्षेत्र वैध रूप से अपनी उत्पादन क्षमताएँ बनाने की आकांक्षा रखता है। चौथा, वैश्विक बुनियादी ढाँचे में विकृतियों को ठीक करके जो औपनिवेशिक युग से विरासत में मिली हैं। दुनिया को तत्काल अधिक कनेक्टिविटी विकल्पों की आवश्यकता है जो रसद को बढ़ाएँ और जोखिमों को कम करें। यह आम भलाई के लिए एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए, जिसमें क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का अत्यधिक सम्मान हो। और पाँचवाँ, अनुभवों और नई पहलों को साझा करके। भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, इसका एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस और गति शक्ति अवसंरचना, सभी एक बड़ी प्रासंगिकता रखते हैं।

मुख्यमंत्री साय ने की राज्योत्सव 2024 की तैयारियों की समीक्षा

4 से 6 नवंबर तक होगा राज्योत्सव का आयोजन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों से राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को अपने -अपने घरों में दीप प्रज्ज्वलित कर दीपोत्सव के साथ राज्योत्सव उत्सव मनाने की अपील की है।ँ

राज्योत्सव के अवसर पर नवा रायपुर, अटलनगर में 10 हजार दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी शहरों और गांव में नागरिकों से 1 नवंबर की शाम को अपने-अपने घरों में दीप प्रज्ज्वलित करने की अपील की है।

बस की सुविधा उपलब्ध रहेगी

नया रायपुर के राज्योत्सव स्थल तक आने जाने के लिए आम जनता को परिवहन की सुविधा रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। राज्योत्सव के

दौरान आयोजन स्थल पर प्रत्येक दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ।

आकर्षण का केंद्र होगा संस्कृति संध्या

सांस्कृतिक संध्या में 4 नवंबर को बॉलीवुड सिंगर शांतनु मुखर्जी (शान) का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

5 नवंबर को बॉलीवुड सिंगर नीति मोहन का कार्यक्रम होगा।

6 नवंबर की शाम को इंडियन आइडल विजेता पवनदीप और अरुनिदिता का कार्यक्रम मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा।

6 नवंबर को राज्य अलंकरण समारोह

राज्योत्सव के आखिरी दिन 6 नवंबर को राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को राज्य अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा।

विकास योजनाओं की होगी प्रदर्शनी

राज्योत्सव स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा प्रमुख विभागीय योजनाओं पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। निजी संस्थानों और पीएसयू संस्थानों के लिए भी हैंगर बनाया जाएगा। कृषि और जल संसाधन विभाग द्वारा भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

प्रदर्शनी में विभागों की नई योजनाएं प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

फैन पार्क होंगे आकर्षण का केंद्र

राज्योत्सव आयोजन स्थल पर शिल्पग्राम, फूड कोर्ट भी बनाया जाएगा। यहां ट्राइबल फूड भी उपलब्ध होगा। बच्चों के लिए फन पार्क भी बनाया जाएगा जहां विभिन्न झूले होंगे।

बैठक में मुख्यमंत्री के कृषि एवं नीति सलाहकार धीरेन्द्र तिवारी, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव पी.दयानंद और राहुल भगत, संस्कृति विभाग के सचिव आचार्य सहित वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना होंगे भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश, 11 नवंबर को लेंगे शपथ

नई दिल्ली। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त होंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर को देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का कार्यकाल 6 महीने का होगा। इससे एक दिन पहले वर्तमान न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ पद मुक्त हो जाएंगे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आठ नवंबर, 2022 को प्रधान न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया था। न्यायमूर्ति खन्ना का प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल छह महीने से कुछ अधिक होगा और वह 13 मई, 2025 को पदमुक्त होंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 'एक्स' पर कहा, ''भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, माननीय राष्ट्रपति, भारत के माननीय प्रधान न्यायाधीश से परामर्श के बाद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को 11 नवंबर, 2024 से देश के प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती हैं। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ है। सीजेआई के पिता जस्टिस देव राज खन्ना भी दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी मां सरोज खन्ना एलएसआर डीयू में लेक्चरार थीं। यहीं से उन्होंने अपनी स्कूली एजुकेशन पूरी की है।

'दाना' का रौद्र रूप, जान-माल की क्षति, जीवन पटरी पर लाने में अरबों होंगे खर्च

नई दिल्ली। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर कई रायों में अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता और ओडिशा में भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द की गई हैं। सैकड़ों ट्रेनें भी रद्द हुई हैं। कुछ गाड़ियों का रूट बदला गया है। तूफान से प्रभावित रायों के कई जिलों में गुरुवार सुबह से ही तेज बरसात हो रही है। शुक्रवार को चक्रवाती तूफान की तबाही देखने को मिल सकती है।

इस दौरान हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी यादा होने की संभावना है। देश में हर साल कोई न कोई चक्रवात आ रहा है। चक्रवाती तूफान के रौद्र रूप से लोगों के जान-माल को भारी नुकसान पहुंचता है। जीवन को फिर से पटरी पर लाने

में अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। दाना से पहले रेमल, तितली, गाजा, बुलबुल व बिपरजॉय जैसे चक्रवाती तूफान भारी तबाही मचा चुके हैं।

इस साल मई में पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान रेमल ने बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया था। रेमल का असर, पूर्वोत्तर रायों में भी देखा गया। पश्चिम बंगाल में रेमल के चलते 24 प्रखंड और 79 नगरपालिका वार्डों में भारी क्षति पहुंची थी। लगभग 30,000 घरों को नुकसान हुआ। हजारों पेड़ गिर गए थे। तूफान की तीव्रता से करीब 1500 बिजली के खंभे गिर पड़े। उस वक्त भी कोलकाता एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन निलंबित किया गया था। रेमल से पहले तौकते, यास, फनी, तितली, गाजा, बुलबुल व बिपरजॉय भारी तबाही मचा चुके हैं।

प्रमुख समाचार

जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में सुरक्षाबलों के वाहन पर हमला

जम्मू। उत्तरी कश्मीर में उड़ी सेक्टर के अंतर्गत गुलमर्ग में गुरुवार को आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला कर दिया। हमले में चार जवान घायल हैं। सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी जारी है। आज के दिन यह दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुबह आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के एक मजदूर को गोली मारकर घायल कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि बिजनौर निवासी प्रीतम सिंह को बटागुंड गांव में आतंकवादियों ने गोली मार दी, मजदूर के हाथ में गोली लगी है। प्रीतम सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। पिछले एक सप्ताह में कश्मीर में गैर-स्थानीय मजदूरों पर लगातार हमले हो रहे है। इससे पहले, गांदरबल में श्रीनगर-लेह हाईवे पर सोनमर्ग के पास गगनगीर इलाके में जेड मोड़ सुरंग निर्माण कर रही कंपनी में कार्यरत प्रवासी मजदूरों पर रविवार की रात आतंकियों ने हमला कर एक डॉक्टर और छह मजदूरों की हत्या कर दी थी। मारे गए मजदूरों में कश्मीरी और गैर कश्मीरी दोनों हैं। प्रवासी मजदूरों पर हाल के वर्षों का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। आतंकी दो बताए जा रहे हैं।

उड़ानों में धमकी,सरकार ने मेटा और एक्स से मांगी मदद

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बम खतरे की झूठी कॉल और संदेशों को गंभीरता से लेते हुए इस साजिश के पीछे के लोगों की पहचान करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने मेटा और एक्स जैसे सोशल मीडिया मंचों से ऐसी कॉल और संदेशों के बारे में जानकारी साझा करने का अनुरोध किया है। सरकार ने कहा कि ये झूठी कॉल जनता के लिए के लिए खतरा हैं और इसलिए उनकी पहचान करने के लिए बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियों से भी सहयोग मांगा गया है। सरकार के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, कुछ लोगों की पहचान की गई है, जो उड़ानों को लक्षित कर बम रखने की झूठी कॉल कर रहे थे और इस मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये झूठी कॉल और संदेश कहां से आए हैं और उनके पीछे कौन है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने मेटा और एक्स से अनुरोध किया है कि वे इन झूठी कॉल और संदेशों से संबंधित डाटा साझा करें। उन्होंने यह भी बताया कि इन कंपनियों को सहयोग करना होगा.

रेलवे चलाएगा सात हजार छठ और दिवाली स्पेशल ट्रेन

नई दिल्ली। रेलवे त्योहार पर यात्रियों को सुरक्षित सफर कराने के लिए सात हजार दिवाली और छठ स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। गुरुवार को कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। केंद्रीय रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से रोज दो लाख यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा बैठक में दो बड़ी रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहली रेल परियोजना के तहत अमरावती के लिए एक रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कृष्णा नदी पर 3.2 किमी लंबा नया रेलवे पुल बनाया जाएगा। यह अमरावती को हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर से जोड़ेगा। इसके साथ ही उत्तर बिहार को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने के लिए नरकटियागंज - रक्सौल - सीतामढ़ी- दरभंगा और सीतामढी - मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। 4553 करोड़ रुपये की लागत से 256 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का दोहरीकरण होने से उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार को फायदा होगा। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि नरकटियागंज-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा और सीतामढी-मुजफ्फरपुर खंड के दोहरीकरण से नेपाल, पूर्वोत्तर भारत और सीमावर्ती क्षेत्रों से कनेक्टिविटी मजबूत होगी.

अजित को लगा बड़ा झटका समीर भुजबल ने छोड़ी पार्टी

मुंबई। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अजित पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। बड़े ओबीसी नेता छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल ने गुट के मुंबई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि भुजबल आगामी विधानसभा चुनाव में नांदगांव निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, नांदगांव सीट फिलहाल एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना के पास है। सूत्रों के मुताबिक, अगर अजित पवार गुट से उनकी उम्मीदवारी नहीं बनती है तो वह शिवसेना के सुहास कांडे के खिलाफ नांदगांव सीट से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। पहले उनके एनसीपी के शरद पवार गुट से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही था। हालांकि, अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं, पुणे जिले के मावल विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) द्वारा निवर्तमान विधायक सुनील शेलके को पार्टी से उम्मीदवार घोषित किए जाने के कुछ ही समय बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और पूर्व राय मंत्री बाला भेगड़े ने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी।

शाह से मिले शिंदे और अजित पवार, मिली ये बड़ी सलाह

महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन नेताओं अजित पवार और एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। इस दौरान शाह ने इन्हें बड़ी सलाह दी है। सूत्रों ने बताया कि शाह ने गठबंधन के नेताओं अजित पवार और एकनाथ शिंदे को सलाह दी है कि वे सुनिश्चित करें कि महायुति के किसी भी गुट से कोई भी बागी चुनाव न लड़े। गठबंधन की चुनावी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए शाह ने तीनों पार्टियों के आंतरिक मतभेद के बिना एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के महत्व पर भी जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) 20 नवंबर को होने वाले राय विधानसभा चुनावों में सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र भर में कई चुनावी रैलियों का नेतृत्व करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार, 5 नवंबर से 14 नवंबर तक, प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न क्षेत्रों में रैलियां करेंगे, न केवल भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए बल्कि पूरे महायुति गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए भी।

भारत से विवाद सुलझाने के लिए झुकता दिख रहा चीन

उमेश चतुर्वेदी

लद्दाख सीमा पर गश्ती को लेकर भारत और चीन के बीच सहमति बन तो गई है, लेकिन उस पर आंख मूंदकर भरोसा करना जल्दबाजी और नासमझी होगी। अतीत में चीन के रवैये को देखते हुए भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का यह कहना समीचीन ही है कि भरोसा बहाली में समय लगेगा। रूस-यूक्रेन और इजराइल-हिजबुल्ला संघर्ष के संदर्भ में भारत और चीन के बीच हुए इस समझौते को बेहतर परिणति ही माना जाना चाहिए।

15 और 16 जून 2020 की रात को बिना हथियारों के भारतीय सैनिकों ने लाल सेना के भले ही दांत खट्टे कर दिए, लेकिन भारतीय विपक्षी दलों ने उस मौके को उत्तेजना की राजनीति के लिए बेहतर मौके के रूप में लिया था। महज एक साल पहले ही तमिलनाडु में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की चर्चित मुलाकात का हवाला देते हुए विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की थी। उनकी मंशा चीन के साथ सीधा युद्ध करने के लिए सरकार को उकसाना रहा। बेशक 1962 जैसी स्थिति नहीं रही। तब से लेकर भारत ने सैनिक और आर्थिक मोर्चे पर लंबा सफर तय कर लिया है। वहीं चीन इस अवधि में दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आर्थिक मोर्चे के लिहाज से देखें तो भारत पांचवें नंबर पर है और सैनिक ताकत के लिहाज से देखें तो चौथे नंबर है। चीन दुनिया के तीसरे नंबर की सैन्य शक्ति है। ऐसे में सीधी सैनिक कार्रवाई की अपनी सीमाएं थीं। इसलिए विपक्षी दलों के तमाम उलाहनों और उकसावों के बावजूद मोदी सरकार ने कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर चीन को घेरना शुरू किया। इसका मतलब यह नहीं कि सीमा पर सैन्य चौकसी कम की गई या सेना को कार्रवाई की छूट नहीं दी गई। गलवान के बाद जब भी जरूरत पड़ी, आधुनिक हथियार विहीन हमारे सैनिकों ने लाल सेना को आगे बढ़ने नहीं दिया।

गलवान कांड के बाद भारत ने चीन के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए। उसमें सबसे पहला कदम यह रहा कि चीन के लिए सीधी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गलवान कांड के बाद से ही पड़ोसी होने के बावजूद दोनों देशों के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है। इस बीच चीन को आर्थिक मंदी का भी सामना करना पड़ा है। चीन को लगता है कि अगर भारत के साथ उसके कारोबारी रिश्ते बढ़ेंगे, तभी वह आर्थिक मोर्चे पर आगे रह सकता है। इसके लिए सीधी उड़ानें एक बड़ा जरिया हो सकती हैं। इसलिए सीमा पर विवाद के बावजूद वह भारत पर गाहे-बगाहे सीधी उड़ान सेवा बहाल करने के लिए कहता रहा है। वह यात्रियों के लिए सीधी उड़ान के साथ ही उनकी संख्या बढ़ाने पर भी जोर देता रहा है। लेकिन भारत ने इसकी लगातार उपेक्षा की। भारत ने एक और कड़ा कदम उठाया। चीन के

लिए सख्त वीजा नियम लागू कर दिए। चीनी नागरिकों के लिए सख्त वीजा नियम होने की वजह से चीन के विशेष इंजीनियरों और तकनीशियनों की भारत में आवाजाही पर एक तरह से पाबंदी ही लग गई।

इसकी वजह से चीनी आर्थिक गतिविधियों में कमी आई। इसके साथ ही भारत ने चीनी कंपनियों के निवेश पर भी कठोर नियम लागू कर दिए। गलवान कांड के तुरंत बाद भारत सरकार ने पड़ोसी देशों की कंपनियों के भारतीय निवेश की जांच प्रक्रिया में पुनरीक्षण और सुरक्षा मंजूरी की एक अतिरिक्त शर्त जोड़ दी। एक तरह से पड़ोसी देशों की कंपनियों के लिए नियम सख्त कर दिए गए। इसका सबसे ज्यादा असर चीनी कंपनियों पर पड़ा। इसकी वजह से भारतीय बाजार में चीनी कंपनियों द्वारा किए जाने वाले अधिग्रहण और निवेश पर लगाम लग गई। इसकी वजह से गलवान कांड के बाद से ही चीनी कंपनियों द्वारा प्रस्तावित अरबों डालर के निवेश की प्रक्रिया अटक गई। जिसका सीधा असर चीन की कंपनियों पर पड़ा और उन्हें आर्थिक दिक्कतें झेलनी पडीं।

गलवान कांड के बाद भारत ने जो बड़ा कदम उठाया था, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। चीन की मोबाइल कंपनियों और एप्स की भारत में गलवान कांड के बाद बड़ी पहुंच बन गई थी। गलवान कांड के तुरंत बाद भारत ने डाटा और गोपनीयता की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए चीन करीब 300 चीनी मोबाइल एप्स पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद साल 2023 में मोदी सरकार ने चीन की स्मार्टफोन कंपनी विवो कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी पर वीजा नियमों का उल्लंघन करने और 13 अरब डॉलर की धनराशि की हेराफेरी का आरोप लगाया था। जिसकी वजह से विवो के भारतीय बाजार पर बड़ा असर पड़ा। इसके साथ ही सरकार ने चीन की दूसरी बड़ी मोबाइल उत्पादक कंपनी शाओमी के खिलाफ कार्रवाई की। शाओमी पर आरोप लगा कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून का उल्लंघन किया है। जांच में यह सही पाया गया और सरकार ने कार्रवाई करते हुए उसकी भारत स्थित करीब 60 करोड़ डॉलर से अधिक की संपत्तियों को जब्त कर लिया। इससे चीन के मोबाइल कारोबार को भारत में बड़ा झटका लगा। वैसे चीन को यहां तक लाने में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बातचीत की बड़ी भूमिका रही है। चीनी विदेश मंत्री चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य हैं।

गुरूचरण सिंह होरा समेत 3 को मिली अग्रिम जमानत

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने ग्रैण्ड ग्रुप के चेयरमेन गुरूचरण सिंह होरा, डायरेक्टर तरणजीत होरा और गुरमीत सिंह भाटिया की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर ली है। उन पर कुछ दिनों पूर्व हैथवे सीसीएन मल्टीनेट प्रा0लि0 कंपनी पर जाली दस्तावेजों के सहारे कंपनी पर कब्जा करने की शिकायत दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट ने दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद इसे सिविल प्रवृत्ति का अपराध मानते हुए मामले में बिना कोई टिप्पणी किए तीनों आवेदकों को अग्रिम जमानत प्रदान करने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि बिलासपुर निवासी अभिषेक अग्रवाल ने कुछ माह पूर्व ग्रैण्ड ग्रुप के चेयरमेन और दो डायरेक्टरों के खिलाफ देवेन्द्र नगर थाने में यह शिकायत की थी कि उन्होंने पंडरी के पगारिया कम्पलेक्स स्थित हैथवे सीसीएन प्रा0लि0 में फर्जी तरीके से कब्जा कर इसका नाम बदलकर ग्रैण्ड अर्श कर दिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल खरे, प्रियंका अग्रवाल और अभिषेक गुप्ता ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश रमेश सिन्हा की अदालत में उक्त तीनों के लिए अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ देवेंन्द्र नगर थाने में ही 10/06/2020 और 26/06/2020 को दो एफआईआर दर्ज है। इसमें उसके द्वारा कंपनी के करोड़ों रूपए गबन कर उसका उपयोग निजी इस्तेमाल के लिए करते हुए कंपनी को भारी नुकसान पहुचाया है। इस दौरान बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि अभिषेक अग्रवाल ने कंपनी का 16.33 प्रतिशत शेयर बेचने की धमकी देते हुए अपने पिता के साथ गजराज पगारिया की उपस्थिती में 100 रूपए के स्टाम्प पेपर पर समझौता पर हस्ताक्षर किया था। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष ने इसे झूठी शिकायत करार देते हुए अपने तीनों मुवक्कील को अग्रिम जमानत देने का आग्रह किया।

विपक्ष के अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव, रितिका दुबे और उप महाधिवक्ता यू.के.एस.चंदेल ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए इससे जांच प्रभावित होने की आशंका जताई। विद्वान न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने दोनों पक्षों कर दलीले सुनने के बाद आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रवृत्ति और इस तथ्य पर विचार करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच विवाद सिविल प्रवृत्ति का है। इसलिए न्यायालय गुणदोष पर कोई और टिप्पणी किए बिना ग्रैण्ड ग्रुप के चेयरमेन गुरूचरण सिंह होरा, डायरेक्टर तरणजीत होरा और गुरमीत सिंह भाटिया को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है।

चावल जमा नहीं करने पर मेसर्स कंसल उद्योग की 6.50 करोड़ की बैंक गारंटी राजसात

■ **धान खरीदी में पाई गई भारी अनियमितता**

रायगढ़। जिले में मेसर्स कंसल उद्योग के खिलाफ धान खरीदी में गंभीर अनियमितताओं के चलते 6.50 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी राजसात की गई है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में हुई जांच में पाया गया कि राईस मिल ने धान का उठाव तो किया, लेकिन उसके मुकाबले बहुत कम चावल जमा किया। इस मामले में संचालक द्वारा दो बार दिए गए कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं देने पर यह सख्त कार्रवाई की गई है।

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में मेसर्स कंसल उद्योग, ग्राम-सांगीतराई की जांच की गई, जिसमें धान के उठाव के बावजूद कम चावल जमा करने की गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इस मामले में राईस मिल को दो बार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, लेकिन संचालक ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे शासन को 6.50 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक क्षति हुई।

कलेक्टर गोयल ने आर्थिक नुकसान को देखते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में

मेसर्स कंसल उद्योग द्वारा कस्टम मिलिंग के अनुबंध में जमा की गई बैंक गारंटी में से 6.50 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली योग्य राशि को की राशि को राजसात करने के लिए जिला विपणन अधिकारी रायगढ़ को आदेशित किया है।

खाद्य अधिकारी ने जानकारी दी कि 2023-24 के खरीफ विपणन वर्ष में पंजीकृत राईस मिल मेसर्स कंसल उद्योग द्वारा 25 अगस्त 2024 को भौतिक सत्यापन किया गया। इसमें पाया गया कि अनुबंध क्रमांक एसी 012024410257 के तहत 27,948.40 क्विंटल धान का उठाव किया गया, जबकि जमा किए जाने योग्य 18,912.68 क्विंटल चावल के मुकाबले केवल 4,049.104 क्विंटल चावल ही जमा किया गया था। इस प्रकार 14,863.58 क्विंटल चावल की कमी पाई गई।

शासन द्वारा धान खरीदी में 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के भुगतान के आधार पर कम पाए गए धान की कुल राशि 6 करोड़ 50 लाख 50 हजार 400 रुपये वसूली जानी है। अनावेदक को 3 सितंबर 2024 और 14 अक्टूबर 2024 को कारण बताओ नोटिस दिए गए, लेकिन मेसर्स कंसल उद्योग के संचालक ने कोई उत्तर नहीं दिया।

धान खरीदी शुरू होने से पहले अवैध परिवहन पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार अब धान खरीदी शुरू करने वाली है। इससे पहले ही धान के बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। इसी बीच वाड्रफनगर के रघुनाथनगर क्षेत्र में एक पिकअप वाहन से अवैध रूप से धान परिवहन किया जा रहा था, जिसपर पुलिस और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 56 बोरी धान को जब्त कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, पिकअप वाहन (क्रमांक सीजी 15 डीबी 7176) उत्तर प्रदेश से अवैध रूप से 56 बोरी धान लेकर आ रही थी। कलेक्टर के निर्देश के बाद इस मामले में सख्त कार्रवाई की गई और पिकअप वाहन को सीज किया गया है। जब्त की गई गाड़ी और धान को थाने में सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि आगे की जांच अभी जारी है।

खनिज विभाग की अवैध रेत खनन परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, 9 गाड़ियां जब्त

बलौदाबाजार। जिले में अवैध रेत परिवहन के मामलों में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। पिछले दो दिनों में हाइवा और ट्रैक्टर सहित 9 रेत से भरी गाड़ियां जब्त की गई।

कलेक्टर दीपक सोनी ने बीते दिनों रेत के अवैध कारोबार के मामले में अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। अवैध रेत के भंडारण, अनुमति और उत्खनन, परिवहन के साथ-साथ रॉयल्टी पर्ची सहित सभी दस्तावेजों की जांच के निर्देश कलेक्टर ने खनिज अधिकारियों को दिया। जिसके बाद मंगलवार और बुधवार रात को ये कार्रवाई की गई।

जिला खनिज अधिकारी केके बंजारे ने बताया कि देर रात और सुबह खनिज विभाग की तरफ से जिले के अलग अलग क्षेत्रों में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के संबध में जांच की गई। जांच के दौरान पलारी तहसील अंतर्गत ग्राम गिधपुरी और लवन तहसील में महानदी क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की गई। 9 गाड़ियां जब्त की गई है।

खनिज अधिकारी ने आगे बताया कि सभी जब्त गाड़ियों को नजदीकी थाना के सुपुर्दगी में रखा गया है। यह सभी कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 से 23 के अंतर्गत किया गया है। वाहन मालिकों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में कलेक्टर सोनी ने कहा कि अवैध खनन पर ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेंगी। अवैध रेत खनन व धंधा करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है।

जिला खनिज अधिकारी केके बंजारे ने बताया कि अनुभाग कसडोल अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आर। आर। दुबे के नेतृत्व में राजस्व की टीम ने बुधवार शाम को कसडोल क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन की जांच की गई। जांच के दौरान महानदी क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन में शामिल 4 हाईवा और 2 ट्रैक्टर को पकड़ा गया। तहसील पलारी अंतर्गत ग्राम गिधपुरी क्षेत्र में खनिज विभाग की टीम की जांच के दौरान ये कार्रवाई की गई। कलेक्टर के निर्देश पर जिले में अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है।

गुरचहवा में शिक्षा व्यवस्था बदहाल एक कमरे में बच्चों की पढ़ाई

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत गुरचहवा में बच्चों की शिक्षा भगवान भरोसे हैं।भले ही कहने को इस क्षेत्र के विधायक प्रदेश के कद्दावर मंत्री हैं।लेकिन उनके क्षेत्र के सरकारी स्कूल की बदहाली किसी से छिपी नहीं है।आज भी यहां के बच्चों के पास पढ़ने के लिए खुद का एक अदद स्कूल भवन नहीं मिल सका है।

गुरचहवा गांव के लोगों को उम्मीद थी स्थानीय विधायक के मंत्री बनने के बाद क्षेत्र का विकास होगा।लेकिन आज सभी की उम्मीदें टूटती जा रही है। प्राथमिक शाला के करीब 55 बच्चे भवन के अभाव में प्रधान पाठक के कार्यालय में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं।

ग्राम पंचायत गुरचहवा का प्राथमिक शाला भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। छत और दीवारें इतनी कमजोर हैं कि कभी भी गिरने का खतरा मंडरा रहा है। लिहाजा बच्चे प्रधानपाठक के कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं।

इस विद्यालय में कई तरह की समस्याएं हैं। जैसे शौचालय पूरी तरह से टूट चुका है। हैंडपंप में पानी नहीं आता।जिस जगह पर बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार किया जाता है,वो भी दयनीय स्थिति में है।गर्मी और ठंड तो जैसे तैसे कट जाती है।लेकिन बारिश के दिनों में स्थिति और भी विकराल हो जाती है।

प्रधान पाठक मंजू भगत ने कहा विद्यालय दो साल पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया था। तब से बच्चों को मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक के कार्यालय में पढ़ाया जा रहा है।

अब सवाल ये है कि इन मासूम बच्चों को कब तक उनका खुद का विद्यालय नसीब होगा या फिर शिक्षा व्यवस्था का यह हाल इसी तरह चलता रहेगा।भले ही क्षेत्र के मंत्री शिक्षा को लेकर बड़ी बातें करते हो,लेकिन जब तक गुरचहवा जैसे स्कूलों का कायाकल्प नहीं होगा,तब तक शिक्षा की नींव मजबूत नहीं होगी।

गैंगस्टर अमन साहू की चुनाव लड़ने वाली याचिका खारिज

बिलासपुर। नामी बदमाश और गैंगस्टर अमन साहू झाखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में खड़ा होना चाहता है। विधायक का चुनाव लड़ने के लिए गैंगस्टर अमन साहू ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अमन साहू की ओर से झारखंड और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई। बुधवार को बिलासपुर हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। अमन साहू की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में इसी विषय को लेकर याचिका लगाई गई है।

झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी और इंडी गठबंधन की वहां पर सीधी टक्कर है। गैंगस्टर अमन साहू भी झारखंड के बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता है। अमन साहू ने चुनाव लड़ने के लिए अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। बिलासपुर हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया। अब अमन साहू के वकील ने झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया है। बिलासपुर हाई कोर्ट से अमन साहू ने चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी। झारखंड के बड़कागांव विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है।

गैंगस्टर अमन साहू फिलहाल रायपुर पुलिस की रिमांड पर है। अमन साहू पर रंगदारी मांगने और कारोबारी पर फायरिंग कराने का आरोप है। कई अन्य मामलों में भी अमन साहू और उसके गैंग से जुड़े लोगों से रायपुर पुलिस पूछताछ कर रही है। अमन साहू की रिमांड अवधि 25 तारीख को खत्म हो रही है। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाना है। कोर्ट के फैसले के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। अमन साहू पर रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में पीआरए ग्रुप के ऑफिस के बाहर फायरिंग करवाने का भी आरोप है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

ईको फ्रेंडली दीयों से जगमग होगी दिवाली

रामानुजगंज। रामानुजगंज में दीपावली के त्यौहार को लेकर तैयारी जोरों पर है। रामानुजगंज की प्रगति वन स्वयं सहायता समूह भी इसके लिए तैयारियों में जुट गया है। यहां की महिलाएं इस बार दीपावली के लिए खास दीये तैयार कर रहीं हैं।इन दीयों की खासियत ये है कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। रामानुजगंज नगर पंचायत अंतर्गत में एसएलआरएम के तहत संचालित प्रगति वन महिला समूह की सदस्य सुनीता देवी ने कहा कि मिट्टी और गोबर से रंग-बिरंगे दीये बना रही हैं। दो महीने से इस काम में जुटी हैं। दीयों को तैयार करने के बाद बाजार में बेचा जाएगा। एक दीये की कीमत दो रुपए रखी गई है। प्रगति वन स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष लाखो पूरी ने कहा कि पिछले चार साल से उनके समूह की महिलाएं दीपावली से पहले दीये बनाने का काम कर रही हैं। समूह अध्यक्ष लाखो पूरी ने कहा दीयों को मार्केट में बेचा जाएगा। मिट्टी और गोबर से दीये बनाकर रंग-रोगन करते हैं। फिर स्टाल लगाकर भी बेचते हैं। ऑर्डर मिलने पर उनके घर तक होम डिलीवरी भी करते हैं।

छत्तीसगढ़ में डांसिंग चोर दुकान से लाखों की चोरी

बेमेतरा। बेमेतरा जिले के साजा में 21 अक्टूबर की रात एक हार्डवेयर दुकान से 4.75 लाख रुपये व तीन नग मोबाइल फोन की चोरी हुई थी। चोरी के बाद चोरों का सीसीटीवी में डांस करते वीडियो सामने आया। इस मामले में अब तक चोर गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं, मौके पर बेमेतरा एसपी रामकृष्ण साहू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने साजा थाना के सहायक उपनिरीक्षक बनवाली राम सोनकर को सस्पेंड कर दिया। क्योंकि, वारदात की रात इसी क्षेत्र में एएसआई बनवाली राम सोनकर की नाइट गश्त में ड्यूटी लगी थी। इसके बाद भी यहां चोरी की वारदात हुई है। एएसआई को पुलिस लाइन बेमेतरा में अटैच किया गया है। इसी प्रकार एसपी रामकृष्ण साहू ने थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मजबूत सूचना तंत्र विकसित कर बेहतर पुलिसिंग करने, रात्रि में गश्त, पेट्रोलिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सिटी कोतवाली बेमेतरा के सीसीटीएनएस ऑपरेटर को केश डायरी कम एंट्री करने के संबंध में एक वेतन वृद्धि रोकने का निर्देश दिया।

ब्रेड काटने वाली चाकू से हमला घायल अस्पताल में भर्ती

गौरेला पेंड्रा मरवाही। पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन के पास भीड़भाड़ वाले इलाके में बीती रात चाकूबाजी की घटना से हड़कंप मच गया। जहां पर कमानिया गेट के पास दाबेली दुकान संचालक और उसके भाई के द्वारा दाबेली खाने आए युवक से पैसे को लेकर विवाद हो गया। जिसके बाद दुकान संचालक और उसके भाई ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया है। फिलहाल, गौरेला पुलिस आरोपियो की सरगर्मी से तलाश कर रही है। दरअसल, पूरा मामला गौरेला के भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन कमानिया गेट के पास का है। जहां पर ठेले पर दाबेली की दुकान लगाने वाले युवक गिरधारी सोनी के दुकान पर पैसे के लेनदेन को लेकर कान्हा नामदेव से विवाद हो गया और वाद विवाद इतना बढ़ गया कि दाबेली दुकान संचालक गिरधारी सोनी और उसका भाई लवकुश सोनी के द्वारा कान्हा नामदेव के गले, सिर और गर्दन पर ब्रेड काटने वाली पतली चाकू से वार कर दिया। जिससे बाद आसपास के लोगों ने कान्हा नामदेव को गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले गए।

शहर में नजर आया तेंदुआ, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट

गरियाबंद। गरियाबंद मुख्यालय में एक बार फिर तेंदुए की आमद ने लोगों की नींद हराम कर दी है। बीती रात तेंदुआ गरियाबंद नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में घूमता रहा और स्थानीय आवारा पशुओं का शिकार करता रहा। तेंदुए की मौजूदगी सीसी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। वन विभाग ने लोगों से तेंदुए को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। खासकर बच्चों और बढ़ों को अकेले में ना घूमने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही तेंदुआ दिखने पर तुरंत विभाग को सूचना देने के लिए कहा है। सूत्रों के अनुसार, तेंदुआ हाइवे किनारे स्थित पहाड़ के खोह में पिछले कई महीनों से डेरा जमाए हुए है। हालांकि, वन विभाग ने तेंदुए की उपस्थिति को दर्शाने वाले चेतावनी बोर्ड लगाकर अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास किया है, लेकिन स्थानीय लोगों में दहशत है। वहीं स्थानीय पार्षद संदीप सरकार ने भी इस स्थिति पर चिंता जताते हुए प्रशासन से सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने तेंदुए को पकड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की मांग की है।

सेवा से बर्खास्त करने से पहले अंतिम सूचना पत्र जारी

गौरेला पेंड्रा मरवाही। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लगातार कई वर्षों से अपने कार्य से अनुपस्थित रहने वाले प्रधान पाठक, दो सहायक शिक्षक एवं सहायक ग्रेड-3 को सेवा से बर्खास्त करने से पहले अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया है। सभी को अलग-अलग सूचना पत्र उनके निवास के पते पर पंजीकृत डाक से भेजा गया है। साथ ही समाचार पत्र के माध्यम से सूचना देते हुए सूचना प्रकाशन की तिथि से 10 दिवस के भीतर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर यह मानते हुए कि शासकीय सेवा में उनकी कोई रूचि नहीं है, उन पर सेवा से बर्खास्त-समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी अंतिम नोटिस के अनुसार गौरीशंकर दीनकर प्रधान पाठक प्राशा डोंगरगढ़ी विकासखण्ड गौरेला जून 2014 से अपने शाला-कार्य से लगातार अनुपस्थित है। निवेदिता लदेर सहायक शिक्षक एल बी प्राशा कोटमीकला पेण्ड्रा जुलाई 2022 से और श्रीमती रानू मसराम सहायक शिक्षक एल बी प्राशा बारीउमरांव पेण्ड्रा जून 2023 से अपने शाला-कार्य से लगातार अनुपस्थित है।

पीएम आवास का घर बनाने महिला सरपंच और उपसरपंच पर पैसा मांगने का आरोप

धमतरी। प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने सख्त निर्देश दिए है। उसके बावजूद कई अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। भोलेभाले लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने पैसों की मांग का मामला धमतरी जिले में आया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा लेने का आरोप लेकर कमार परिवार जिला पंचायत पहुंचा। पति पत्नी ने सरपंच और उप सरपंच पर पैसा मांगने का आरोप लगाया। मगरलोड इलाके के कोरगांव के रूपलाल कमार ने बताया कि वह मजदूरी करके घर चलाता है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पिछले 25-30 वर्षों से झोपड़ी में रहता था।

पीड़ित रूप लाल ने आगे बताया कि

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का लाभ मिलने की सूची में उसका नाम आया। पहली किश्त मिल गई है। लेकिन दूसरी किश्त आने से पहले सरपंच और उपसरपंच पैसों की डिमांड कर रहे हैं। 10 हजार रुपये मांगे थे जिस पर किसी तरह जुगाड़ कर 5 हजार रुपये उन्हें दिया गया। लेकिन दोनों और रुपये देने की मांग कर रहे हैं।

रूपलाल की पत्नी संतोषी कमार ने बताया कि सरपंच और उपसरपंच आवास नहीं बनने दे रहे हैं। पहली किश्त का पैसा आ गया है। लेकिन दूसरी किश्त की राशि के लिए नाम काट दिया गया है। जिससे हम परेशान है।

इस मामले पर जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव ने कहा कि विकासखंड मगरलोड के कोरगांव से एक कमार परिवार ने पैसों को लेकर सरपंच की शिकायत की है। जांच करवाई जा रही है। जांच के बाद आगे पता चलेगा।

नाले में तेंदूपत्ता मिलने पर मंत्री वर्मा ने दिलाया भरोसा

गड़बड़ी पाए जाने पर होगी जांच

नारायणपुर। नारायणपुर में नाले में सैकड़ों बोरा तेंदूपत्ता फेंके जाने के मामले में मंत्री टंकराम वर्मा ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से चर्चा करेंगे, अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो जांच करवाएंगे।

मंत्री टंकराम वर्मा आज नारायणपुर में आयोजित आवास मेला में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा की। दौरे के संबंध में उन्होंने बताया कि हमने 18 लाख पीएम आवास देने की बात की थी। मुख्यमंत्री ने अपने वादा को पूरा किया है। आज हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपी जाएगी।

वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन दाखिल करने और शक्ति प्रदर्शन को लेकर मंत्री ने

कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से ही शक्तिहीन हो चुकी है। उसमें एनर्जी आने वाला नहीं है, कांग्रेस से लोगों का भरोसा उठ गया है।

सरकार द्वारा कर्मचारियों को सौगात देने पर टंकराम वर्मा ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सब का विश्वास इस अवधारणा पर बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ का समग्र विकास हो, और सुख, शांति और समृद्धि आए। सभी वर्ग के लिए सबके हितों का ध्यान रखा जाए।

उन्होंने कहा कि भाजपा किसी वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करती। हमेशा प्रदेश प्राथमिकता है, उसको तय करते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। वहीं दीपक बैज के विजय बघेल को लेकर किए गए वीडियो पोस्ट पर कहा कि सरकार अपनी हर घोषणा को गंभीरता से लेती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में घोषणा की थी। सभी बड़ी घोषणा को 100 दिन के अंदर पूरा कर दिया।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री ने किया श्री सत्य साईं संजीवनी नर्सिंग कॉलेज का उदघाट्न

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्री

सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल नवा रायपुर परिसर में श्री सत्य साईं संजीवनी नर्सिंग कॉलेज का उदघाट्न किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्री सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल नवा रायपुर के चेयरमेन डॉ सी. श्रीनिवास भी उपस्थित हैं।

रेरा द्वारा प्रावधानों का पालन में चूक करने वाले 412 बिल्डर्स को नोटिस जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन में चूक करने वाले 412 बिल्डर्स को नोटिस जारी किया गया है। संबंधित बिल्डर्स द्वारा समय पर त्रैमासिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट, प्रस्तुत नहीं किया गया है। कुछ प्रोजेक्ट्स निर्धारित समयावधि के बाद भी पूर्ण नहीं हुए है उन्हें भी नोटिस दिया गया है। 15 दिवस के भीतर ऑनलाइन जानकारी अपडेट करने तथा प्रोजेक्ट अपूर्ण होने की स्थिति में कारण बताते हुए समय विस्तारण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये गये हैं। 15 दिवस के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में रेरा द्वारा संबंधित बिल्डर्स/प्रमोटर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए कार्यवाही की जाएगी।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद छत्तीसगढ़ में मनाएंगे दीपावली

रायपुर। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद छत्तीसगढ़ में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक दीपावली महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे रायपुर, बिलासपुर, सिमगा, बेमेतरा, कबीरधाम और अन्य स्थानों पर प्रवास करेंगे। इन जगहों पर आयोजित महाकाली जन्मोत्सव-गोवर्धन पूजा में शामिल होंगे।

एसीबी की टीम ने 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

कांकेर। जिले के नक्सल प्रभावित आमाबेड़ा क्षेत्र में जगदलपुर से आई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए आमाबेड़ा के तहसील कार्यालय में पदस्थ लिपिक परमेश्वर गौतम एवं एक उसके सहयोगी कर्मचारी रेखचंद यादव को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पूरा ममला सर्पदंश से मृत्यु पश्चात् शासन से मिलने वाली 4 लाख रूपये मुआवजा राशि भुगतान के एवज में लिपिक परमेश्वर गौतम कार्यालय के बाहर फूफगांव मार्ग में पीड़ित को बुलाकर रिश्वत ले रहा था, इसी दौरान 10 हजार रुपये रिश्वत ले रहे उसके सहयोगी कर्मचारी रेखचंद यादव के साथ एसीबी की टीम ने दोनो आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी अमर सिंह हुपेण्डी ग्राम अर्रा, तहसील आमाबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो जगदलपुर में शिकायत की गई थी, कि उनके चचेरे भाई राधेश्याम हुपेण्डी की सर्पदंश से मृत्यु पश्चात् शासन से मिलने वाली 4 लाख रूपये मुआवजा राशि की प्रक्रिया पूरी कराने के एवज में आमाबेड़ा तहसील कार्यालय का बाबू परमेश्वर गौतम ने 25 हजार रूपये रिश्वत की मांग की है, जिस पर प्रार्थी ने 4 हजार रुपए पहले ही दे दिया था। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था, और आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन के पश्चात एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आज गुरूवार को ट्रेप आयोजित कर आरोपी परमेश्वर गौतम को प्रार्थी से अगली किश्त के रूप में 10 हजार रूपये रिश्वत अपने सहयोगी रेखचंद यादव के माध्यम से लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। दोनों आरोपी परमेश्वर गौतम एवं रेखचंद यादव को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जा रही है।

कवर्धा के सहकारी बैंक में 30 लाख रुपये चोरी की कोशिश नाकाम

कबीरधाम। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव के कवर्धा स्थित अमानत शाखा में चोरी की कोशिश हुई है। यह बैंक कवर्धा शहर के रायपुर रोड़ स्थित एक मॉल में है। बताया जा रहा है कि बैंक में बुधवार रात बुधवार करीब 11 बजे एक अज्ञात चोर घुस गया था। इस चोर ने बैंक के मेन गेट के ताला को बिजली के कटर से काटकर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद बैंक के भीतर लॉकर तक पहुंच गया था। हालांकि, चोर के हाथ कुछ भी नहीं लग सका है। रुपये, सोने-चांदी के जेवरात तक नहीं पहुंच सका। इसके बाद वह भाग गया। बुधवार की सुबह जब बैंक खुला तो इस घटना के बारे में पता चला है। मौके पर सिटी कोतवाली पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें एक अज्ञात चोर दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि इस बैंक के लॉकर में करीब 30 लाख रुपये नकद रखे हुए थे। इसके अलावा महंगे सोने-चांदी के गहने भी थे। बैंक की सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस समय की यह घटना है, उस समय गार्ड मौजूद नहीं था। बता दें कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में ज्यादातर किसानों के खाते होते हैं। ये राज्य स्तर पर संचालित किए जाते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक की तरह यहां कई प्रकार की सुविधा व सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है। यही कारण है कि ऐसे बैंक चोरों के निगाह में हमेशा रहते हैं।

कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी को बताया निष्क्रिय, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया पलटवार, कहा-

सुनील सोनी ने सांसद निधि का शत प्रतिशत किया उपयोग

रायपुर। रायपुर-दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुनील सोनी को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा को टिकट दिया है। चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, दोनों पार्टियों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच आज रायपुर दक्षिण विधानसभा के पूर्व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी पर कांग्रेस के लगाए आरोपों का जवाब दिया।

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव को लेकर एक प्रेसवार्ता में बीजेपी के पूर्व सांसद सुनील सोनी का समर्थन करते हुए कहा कि सुनील सोनी ने रायपुर शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने उन पर कांग्रेस द्वारा निष्क्रियता के आरोपों को गलत बताया और कहा कि सुनील सोनी ने 100 प्रतिशत सांसद निधि का उपयोग किया है।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सुनील सोनी रायपुर के विकास पुरुष हैं और उनके कार्यकाल में शहर का स्वरूप बदला है। उन्होंने रायपुर में सिटी बस सेवा की शुरुआत, 1000 करोड़ के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, और अमृत मिशन योजना के तहत बड़े पैमाने पर किए गए कामों का जिक्र किया। साथ ही, उन्होंने बताया कि सुनील सोनी ने विभिन्न पदों पर जनता की सेवा की है और उनकी उपलब्धियों के आधार पर रायपुर दक्षिण की जनता उन्हें भली-भांति जानती है। सांसद अग्रवाल ने यह भी कहा कि रायपुर दक्षिण में सुनील सोनी के नेतृत्व में विकास कार्यों को और आगे बढ़ाया जा

सकता है और उनके काम की तुलना में कांग्रेस के प्रत्याशी को कोई पहचान नहीं है।

गौरतलब है कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आकाश शर्मा को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद कहा था कि आकाश युवा प्रत्याशी हैं, मजबूत चेहरा हैं, और युवाओं के बीच अच्छी पकड़ रखते हैं। उन्होंने दक्षिण विधानसभा में लगातार युवाओं के बीच काम किया है। एनएसयूआई अध्यक्ष और युवा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनका अनुभव पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। वहीं, बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी को लेकर उन्होंने कहा था कि भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी को तय करना है कि बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में लड़ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। क्षेत्र की जनता जानती है कि सुनील सोनी सबसे निष्क्रिय प्रत्याशी हैं। महापौर और सांसद रहते हुए उन्होंने विधानसभा के लिए कुछ नहीं किया है। जनता के लिए कुछ नहीं किया है। पूरी तरह से निष्क्रिय प्रत्याशी रहे हैं। इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस मजबूती के साथ तैयारी कर रही है और इस समय जनता बदलाव चाहती है, जिसका लाभ कांग्रेस को जरूर मिलेगा।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर दुर्ग सांसद विजय बघेल और बीएड डीएड के अभ्यर्थियों की बातचीत के वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वादे जनता से किए जाते हैं और उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इसमें समय लगता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने जो वादे किए हैं, वे सभी पूरे किए जाएंगे। उनका बयान यह संकेत देता है कि पार्टी वादों को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन उनकी पूर्णता के लिए धैर्य आवश्यक है।

सीएम साय की अध्यक्षता में खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की बैठक

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 20वीं बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में विभिन्न खनिज परियोजनाओं और अधोसंरचना के लिए महत्वपूर्ण राशि स्वीकृत की गई।

बैठक में डोंगरगढ़-कबीरधाम-मुंगेली-कटघोरा रेलमार्ग के लिए भू-अर्जन और प्रारंभिक निर्माण कार्य के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इसके अलावा, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म के खनिज अन्वेषण और खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए 83 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से खनिज विकास निधि सलाहकार समिति के पूर्व निर्णयों और राशि के उपयोग के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने निधि में उपलब्ध राशि को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में वृहद अधोसंरचना निर्माण की परिकल्पना पर विचार करने के निर्देश दिए।

बैठक में राज्य में खनिज राजस्व में वृद्धि की संभावनाओं के अध्ययन और खनन क्षेत्र में सुधार हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं की सेवाएं लेने के लिए 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया।

गौरतलब है कि खनिज विभाग द्वारा प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले कुल खनिज राजस्व की 5त्न राशि खनिज विकास निधि मद में आरक्षित रहती है। यह निधि सलाहकार समिति की अनुशंसा अनुसार विभिन्न आवश्यक परियोजनाओं के लिए राशि प्रदान की जाती है। इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव द्वय पी। दयानंद, राहुल भगत, सचिव वित्त शारदा वर्मा, संचालक खनिज सुनील जैन, संयुक्त संचालक खनिज अनुराग दीवान एवं खनिज संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

रायपुर दक्षिण विस से कांग्रेस प्रत्याशी को बाहरी बताने पर भूपेश बघेल का पलटवार

■ कहा- जो बाहरी कह रहे हैं, उनकी जड़ें कहां है?

रायपुर। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा बाहरी प्रत्याशी बताए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति बता दो, जिसकी गांव में जमीन या घर ना हो। जो बाहरी कह रहे हैं, उनकी जड़ें कहां है? सबकी जड़े गांव से जुड़ी हुई है।

वायनाड में प्रियंका गांधी के नामांकन रैली में शामिल होकर रायपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने रायपुर दक्षिण विस सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी को बाहरी बताए जाने पर कहा कि आकाश शर्मा गुंडरदेही से हैं। (सुनील) सोनी जी कहां से आए हैं, या बृजमोहन अग्रवाल कहां से है? वह भी गांव से आए हैं। छत्तीसगढ़ के किस गांव से आए हैं?

बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा उप

चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी के शुभमुहूर्त में नामांकन दाखिल करने के दौरान मौजूद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला, इसलिए एक ऐसे युवा को प्रत्याशी बनाया, जिसे रायपुर शहर के एक प्रतिशत जनता भी नहीं जानती है, ना ही पहचानती है। उनका दक्षिण विधानसभा के विकास में कोई योगदान भी नहीं है।

वहीं सूरजपुर में मामले में एसपी-कलेक्टर के ट्रांसफर पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के बयान का समर्थन करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि अजय चंद्राकर ठीक कह रहे हैं, आगे बढ़कर के कहें कि सरकार ही बर्खास्त किया जाए। राज्यपाल खुद जिलों में बैठक ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में घर-कार्यालय जलाने की बात हो रही है। (भाजपा) हाईकमान अजय चंद्राकर की बात सुने। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वायनाड से चुनाव लड़ रहीं प्रियंका वाड्रा को लेकर कहा कि प्रियंका बहुत समय से राजनीति में हैं। सबके लिए चुनाव प्रचार करती रही हैं। कल उनका नामांकन था, ऐतिहासिक दिन था। जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। रैली में लाखों लोगों की भीड़ मे थी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए आकाश शर्मा के नामांकन में शामिल होने की बात कहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने युवा नेता आकाश शर्मा पर दांव लगाया है। एक बुजुर्ग के सामने एक युवा नेता मैदान में है।

दो दिवसीय प्रवास पर आज छत्तीसगढ़ आ रहीं राष्ट्रपति मुर्मू

रायपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के लिए राजधानी रायपुर तैयार है। सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए शहर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। अधिकारी मौका मुआयना करते हुए नजर आ रही छोटी-बड़ी खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश दे रहे हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दो दिवसीय दौरा शुक्रवार से शुरू हो रहा है। कमोबेश एक साल के अंतराल के बाद हो रहे राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है, जिसके लिए आज फाइनल मॉकड्रिल किया गया।

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के दौरे के मद्देनजर शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच चार बार रिंग रोड नंबर 1 बंद रहेगा। राष्ट्रपति का काफिला डीडीनगर, गोलचौक जैसे व्यस्त इलाके से होकर गुजरेगा। रूट प्लान में काफिला गुजरने के आधे घंटे पहले रास्ते बंद रहेंगे।

राष्ट्रपति सुरक्षा की पूरी कमान रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा के हाथों में रहेगी। उनके निर्देशन में शहर के अलग-अलग इलाकों में एक हज़ार से अधिक पुलिस जवान और सौ से अधिक पुलिस के आला अधिकारी सुरक्षा संभालेंगे। इसके लिए अन्य जिलों से अतिरिक्त बल भी बुलाया गया है।

दौरे का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

25 अक्टूबर- सुबह 11 बजे: राष्ट्रपति का रायपुर एयरपोर्ट पर आगमन।

सुबह 11:30 बजे- रायपुर एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी।

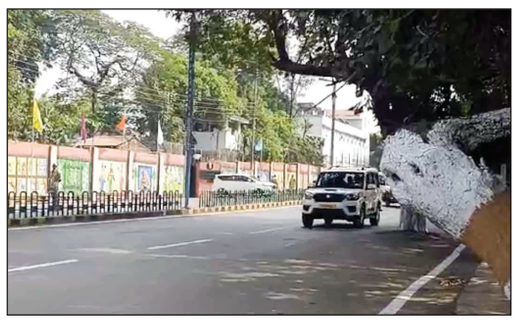

दोपहर 1 बजे- एम्स से रवाना होकर राजभवन पहुंचेंगी।

दोपहर 3 बजे- एनआईटी रायपुर के 14वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी।

शाम 4:30 बजे- नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में स्थानीय आदिवासियों से मुलाकात।

शाम 6 बजे- राजभवन लौटेंगी और रात्रि विश्राम करेंगी।

26 अक्टूबर- सुबह 9 बजे- विवेकानंद सरोवर, रायपुर का दौरा।

सुबह 10 बजे- रायपुर एयरपोर्ट से भिलाई के लिए प्रस्थान।

सुबह 11 बजे- आईआईटी भिलाई के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी।

दोपहर 1:30 बजे- भिलाई से वापस रायपुर स्थित राजभवन लौटेंगी।

दोपहर 3:30 बजे- पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति चिकित्सा एवं आयुष विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी।

शाम 5 बजे- दीक्षांत समारोह के बाद दिल्ली के लिए रायपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के प्रवास के संबंध में राज्यपाल डेका ने तैयारियों की समीक्षा की

रायपुर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर राज्यपाल श्री रमेन डेका ने राजभवन में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि अधिकारियों-कर्मचारियों को जो दायित्व सौंपे गए है उनको पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करे।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु 25 और 26 अक्टूबर को अपने दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राजभवन में ठहरेंगी। इस दौरान राजभवन द्वारा की गई सभी व्यवस्थाओं की तैयारी के संबंध में श्री डेका को अवगत कराया गया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री यशवंत कुमार, विधिक सलाहकार श्री भीष्म प्रसाद पाण्डेय, संयुक्त सचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम सहित राजभवन के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

शिक्षकों का हल्लाबोल, छत्तीसगढ़ के 1 लाख 80 हजार शिक्षक हड़ताल पर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन है। प्रदेश के सभी जिलों में धरना रैली की तैयारी है। संविलियन के बाद पुरानी सेवा को शून्य करने से आये वेतन विसंगतियों से शिक्षक नाराज हैं। आज सामूहिक अवकाश लेकर शिक्षक हड़ताल पर हैं। शिक्षकों की हड़ताल से स्कूल भी बंद हैं।

छग शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांत संचालक वीरेंद्र दुबे ने बताया कि शिक्षकों में संविलियन के बाद वर्षों की पुरानी सेवा को शून्य किये जाने से बड़ी वह नाराज हैं। इसके कारण कर्मचारियों को मिलने वाले त्रिस्तरीय क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान से वंचित होना पड़ रहा है।

शिक्षकों का यह भी कहना है कि ओपीएस में पूर्ण पेंशन नहीं मिल पाएगी। ग्रेज्युटी,कैशलीव जैसी सुविधाओं में भी आंशिक लाभ ही मिल पायेगा, क्योंकि इन सबका पूर्ण लाभ लेने के लिए तय समयावधि की सेवा जरुरी होती है।

शिक्षकों का संविलियन आंदोलन के बाद यह पहला आंदोलन है, जिसमें सभी प्रमुख शिक्षक संगठन एक साथ एक मंच पर आकर शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाकर आंदोलन कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांत संचालक वीरेंद्र दुबे, संजय शर्मा,मनीष मिश्रा व विकास राजपूत के नेतृत्व में इसे पूर्व सेवा गणना मिशन का नाम दिया गया है। आज छत्तीसगढ़ के हर जिले में जिलास्तरीय धरना प्रदर्शन कर रैली निकालने की तैयारी है। यह संविलियन आंदोलन के बाद पहला बड़ा प्रदर्शन है, जिसमें एल बी संवर्ग के सभी सहायक शिक्षक, विज्ञान सहायक, प्रधानपाठक (प्राथमिक/माध्यमिक), संकुल समन्वयक,शिक्षक, लाइब्रेरियन, व्याख्याता, प्रभारी प्राचार्य शामिल हो रहे हैं।

शिक्षक आंदोलन में शामिल होने जा रहे कर्मचारी हुए हादसे का शिकार

कांकेर। प्रदेशभर के शिक्षक आज अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे 6 शिक्षकों के साथ सड़क हादसा हो गया। पंखांजूर से कांकेर जिला मुख्यालय जाते वक्त दुर्गुकोंदल थानाक्षेत्र के पुत्तरवाही के पास शिक्षकों की कार पेड़ से जा टकराई। इस घटना में कार बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कार में सवार सभी शिक्षकों को मामूली चोट आई है। दरअसल, प्रदेश के शिक्षकों में संविलियन के बाद उनकी वर्षो की पुरानी सेवा को शून्य किये जाने से बड़ी नाराज़गी है। इसके कारण उन्हें कर्मचारियों को मिलने वाले त्रिस्तरीय क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान से वंचित होना पड़ रहा है।

चक्रवाती तूफान दाना का पूरे छत्तीसगढ़ में दिखेगा असर, बस्तर में अलर्ट

रायपुर। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर चक्रवाती तूफान दाना में तब्दील होने वाला है। इस तूफान का असर छत्तीसगढ़ के मध्य, दक्षिण और उत्तर छत्तीसगढ़ में 25 और 26 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। इस दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होगी। कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे।

चक्रवाती तूफान दाना का ज्यादा असर 24 की रात और 25 अक्टूबर की सुबह पूरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर ज्यादा देखने को मिलेगा। इस दौरान यहां पर 100 से 110 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।

मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला बताया कि गुरुवार को एक चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में तब्दील होने की प्रबल संभावना है। लेकिन इसका ज्यादा असर छत्तीसगढ़ में फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इसकी वजह से दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ में 25 और 26 अक्टूबर को बारिश होगी। कुछ जगहों पर बादल छाए रहने की संभावना है।

चक्रवात दाना के आने से पहले ओडिशा के केंद्रपाड़ा तट पर समुद्र में ऊंची लहरें देखी गई। भद्रक के धामरा में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो रही है। वहीं चक्रवात के आने से पहले पश्चिम बंगाल के दीघा में हल्की बारिश हुई। शुक्रवार सुबह ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छत्तीसगढ़)
Email - ID: ee-res.kondagaon@nic.in, Ph. No.-07786-296017

मैनुअल पद्धति वर्ष 2024-25 हेतु सूचना क्रमांक-19
निविदा आमंत्रण

क्रमांक / 19 / व.ले.लि./ नि.प्र./ग्रा.यां. सेवा/ 2024-25 कोण्डागांव, दिनांक 21/10/2024

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत डी एवं उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु सामग्री प्रदाय हेतु मैन्युअल के अपेंडिक्स 2.15 के अनुसार प्रपत्र सी में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय में प्राप्त होने की **अंतिम तिथि 28/10/2024 शाम 5.00 बजे** तक:-

स. क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत प्रति कार्य (रूपये लाख में)	रिमार्क (निविदा क्रम)
1	2	3	4
1	सामुदायिक भवन निर्माण शौचालय सहित- (समूहों के लिये आजीविका कार्यकलाप के लिये वर्क शेड निर्माण कार्य/सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य) विद्युतीकरण कार्य सहित, (शेष कार्य हेतु) मुलमुला, वि.ख. कोण्डागांव	9.01	तृतीय दौर
2	समुदाय के लिये खेल मैदान निर्माण कार्य भाग-1 (पवेलियन, शौचालय, सिटिंग गैलरी, आहता, नलकूप खनन कार्य) विद्युतीकरण कार्य सहित, (शेष कार्य हेतु) रांधना, वि.ख.माकड़ी	16.23	छठवां दौर
3	समुदाय के लिये तटबंध निर्माण (बुढ़ासागर तालाब) (शेष कार्य हेतु) माकड़ी	9.88	छठवां दौर

2 उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी विभागीय वेबसाइट http://res.cg.gov.in दिनांक 22/10/2024 से देखी एवं डाऊनलोड की जा सकती है।
3 भुगतान मनरेगा प्रक्रिया के तहत् किया जावेगा।

कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग
कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव

जी-242503393/4 विकास का वादा- मजबूत इरादा Credible Chhattisgarh विश्वसनीय छत्तीसगढ़

एशिया की ओर बढ़ती वैश्विक धुरी के संकेत

राजेश बादल

ब्रिक्स शिखर बैठक से ठीक पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान गंभीर इशारा करता है और वैश्विक समीकरणों की पड़ताल भी चाहता है। सर्गेई ने पश्चिमी देशों का नाम लिए बिना साफ-साफ कहा है कि भारत, चीन और रूस की दोस्ती मजबूत हो रही है और यह बहुत आगे जाएगी। सर्गेई के इस कथन का सीधा-सीधा अर्थ यही है कि अब आने वाला समय अमेरिकी चौधराहट के लिए शुभ संकेत नहीं है। पश्चिमी राष्ट्रों और यूरोपीय मुल्कों के लिए इसमें अनेक संदेश छिपे हैं। आने वाले दिनों में यह बयान रूसी रवैये में छिपी हुई एक खास नरमी की ओर इशारा करता है। सर्गेई लावरोव कहते हैं कि ब्रिक्स का उद्देश्य किसी से संघर्ष करना नहीं है। यदि इस अंतरराष्ट्रीय संगठन में पश्चिम के राष्ट्र शामिल नहीं हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उनके विरोधी हैं या फिर उनसे टकराव लेना चाहते हैं। हकीकत तो यह है कि इसमें शामिल देश अपनी भौगोलिक निकटता और साझा विरासतों का बेहतर भविष्य के लिए लाभ उठाना चाहते हैं। यदि सर्गेई के कूटनीतिक संदेश को हम पढ़ना चाहें तो सरल भाषा में कह सकते हैं कि पश्चिमी देशों की दादागीरी के दिन लद गए। अब एशिया की बारी है। वैसे ब्रिक्स की जन्म गाथा बेहद दिलचस्प है। रूस, चीन और भारत ने करीब चौंतीस साल पहले एक नया संगठन बनाया। उस दौर की अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनजर अमेरिका संसार का चौधरी बन बैठा था और आबादी, क्षेत्रफल तथा संसाधनों की दृष्टि से भारत, चीन और रूस से कहीं पीछे था। यह स्थिति एशिया के इन उप सरपंचों को रास नहीं आ रही थी। इसलिए इन त्रिदेवों को एक मंच पर आना ही था। उस दौर में भारत तथा चीन के संबंधों में आज की तरह तनाव का जहर नहीं घुला था। इसके बाद इस तिकड़ी के साथ ब्राजील भी आ गया। इससे इन चार देशों ने नई शताब्दी में प्रवेश करते-करते संसार को चौंका दिया। निवेशक बैंक गोल्डमैन सैक्स ने 2001 में इन चार देशों को सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया था। अगले आठ साल में इन चार राष्ट्रों ने 2009 में ब्रिक्स नामक इस विराट संस्था को आकार दिया, जब 2010 में दक्षिण अफ्रीका को प्रतिनिधित्व मिला और इस तरह अफ्रीकी देश भी इस संगठन के बैनर तले आ गए। मौजूदा साल में चार नए देश इसका अंग बने। मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात ने इस संस्था को इतना विराट आकार दिया कि यह यूरोपीय यूनियन को पछाड़कर संसार का तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक संगठन बन गया। इन चार राष्ट्रों के ब्रिक्स का सदस्य बनने के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन रूस में हो रहा है। ब्रिक्स के आंतरिक ताजा समीकरण भारत की स्थिति को तनिक भारी बनाते हैं। रूस के साथ भारत के गहरे पारंपरिक रिश्ते हैं। ब्राजील और अफ्रीका के साथ भारत के ऐतिहासिक और कूटनीतिक संबंध चीन की तुलना में बेहतर हैं। भारत अकेला देश है, जिसके ईरान से सदियों पुराने गहरे आध्यात्मिक और आर्थिक रिश्ते रहे हैं। ब्रिक्स की पिछली बैठक की अध्यक्षता कर रहे चीनी राष्ट्रपति ने ईरान पर डोरे डालने का प्रयास किया तो ईरानी राष्ट्रपति ने इशारों में स्पष्ट कर दिया था कि क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय टकरावों से विश्व शांति के लिए कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। चीन की दाल तो नहीं गली, पर यह साफ हो गया कि ब्रिक्स के अलावा वह अरब देशों में भी प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। पेंच यह है कि सऊदी अरब खुलकर अमेरिका के पक्ष में है। इसलिए उसके पड़ोसी ईरान पर डोरे डालना चीन के अपने हित में है। तुर्की और मलेशिया से उसने पहले ही पींगें बढ़ा रखी हैं। सिर्फ भारत ही ऐसा देश है, जिसके साथ चीन अपने को असहज पाता है। भारत एक तरफ ब्रिक्स में प्रभावी भूमिका में है तो दूसरी ओर क्वाड में वह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ है। चीन की उलझन का यह बड़ा कारण है। ब्रिक्स की पिछली बैठक से पहले ग्रुप-7 के शिखर सम्मेलन में चीन ने भारत पर सांकेतिक हमला बोला था। लेकिन उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। पाकिस्तान को चीन छोड़ नहीं सकता और पाकिस्तान ने भारत से दोस्ती नहीं रखने की स्थायी कसम खा रखी है। ऐसे में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान संकेत देता है कि चीन और भारत आने वाले दिनों में दोस्ती का एक कदम और बढ़ाते दिखाई दें। यदि ऐसा होता है तो यह पश्चिमी और यूरोपीय देशों को रास नहीं आएगा, क्योंकि इससे उनका आधार कमजोर होगा और वैश्विक धुरी एशिया के पाले की ओर खिसकती दिखाई दे सकती है। इसलिए भारत के लिए सर्गेई के बयान में दो संदेश छिपे हैं। एक तो यह कि चीन समझ गया है कि भारत को साधे बिना वह अमेरिका की चौधराहट को चुनौती नहीं दे सकता। आने वाले दिनों में वह रूस की मध्यस्थता में भारत के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में गंभीर हो जाए। दूसरा यह कि चीन के सामने साफ हो गया है कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका को छोड़ना संभव नहीं है।

चंद्रबाबू नायडू के बयान के मायने

अजय बोकिल

देश के दक्षिणी राज्यों से आबादी बढ़ाने की जो आवाजें उठी हैं, क्या वो 'जनसंख्या जिहाद' का पलटवार है या भविष्य में राजनीतिक सत्ता सूत्र अपने हाथों में रखने की प्री प्लानिंग है अथवा देश में क्षेत्रवार आबादी के असंतुलन से होने वाले व्यापक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों के मद्देजर ऐहतियाती उपाय अभी करने का आग्रह है, इसे हमे गहराई से समझना होगा।

दक्षिणी राज्यों के दो मुख्यमंत्रियों ने हाल में अपने प्रदेश के लोगों से आबादी बढ़ाने की जो अपील की है, वो भारत में 'जनसंख्या विस्फोट' को रोकने के लिए अब तक चली आ रही 'परिवार नियोजन' थ्योरी के ठीक विपरीत है। तो क्या इन नेताओं को बेतहाशा बढ़ती आबादी से जुड़े खतरों का भान नहीं है या फिर वो सीमित परिवारों के आग्रह में छिपे आसन्न खतरों को भांप कर ऐसा कह रहे हैं?

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाल में कहा कि अब उनकी सरकार पुराने कानून में बुनियादी बदलाव कर उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति देगी, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हों। अभी तक दो से ज्यादा बच्चों वाले माता-पिता स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते थे। नायडू ने इस के पक्ष में दलील दी कि वृद्धावस्था की समस्या के संकेत दक्षिण भारत, खासतौर से आंध्र प्रदेश में दिखने लगे हैं। जापान, चीन और कुछ यूरोपीय देश पहले ही इस समस्या का सामना कर रहे हैं, जहां बुजुर्गों की संख्या अधिक है। दक्षिण भारत में यह समस्या और गंभीर है क्योंकि युवा रोजगार की तलाश में बाहर चले जाते हैं। परिणामस्वरूप कई गांवों में तो अब बुजुर्ग ही रह गए हैं। नायडू ने यह भी कहा कि दक्षिणी राज्यों में प्रजनन दर 1.6 तक गिर चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत 2.1 से काफी कम है। अगर यह और घटती है, तो 2047 तक बुजुर्गों की संख्या अधिक होगी, जो कि वांछनीय नहीं है।

चंद्रबाबू के बयान के दूसरे ही दिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने भी लगभग उसी बात को दोहराया। हालांकि उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से राजनीतिक था। हिंदू धार्मिक मामलों के विभाग के तत्वावधान में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा- संसदीय परिसीमन प्रक्रिया से दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने और छोटा परिवार का विचार छोड़ने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अतीत में, बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ों को 16 बच्चों का नहीं बल्कि 16 तरह की संपत्ति अर्जित करने और खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद देते थे। अब उन्हें सचमुच 16 बच्चे पैदा करने चाहिए, न कि एक छोटा और

खुशहाल परिवार रखना चाहिए।

वैसे नायडू के कथन में सच्चाई है कि बेशक आज भारत सबसे ज्यादा युवाओं का देश है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 65 फीसदी 35 साल के नीचे की है। लेकिन तीस साल बाद यही आबादी 65 वर्ष की होगी। यानी भारत में हर पांचवा शख्स बुजुर्ग होगा। यह आबादी करीब 35 करोड़ होगी। यह वो आबादी होगी, जो सेवानिवृत्त अथवा कम कार्यक्षम लोगों की होगी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां आबादी का अर्थ जनशक्ति से ज्यादा 'वोट' हो चुका है, वहां जनसांख्यिकीय संतुलन का अर्थ राजनीतिक सत्ता को कायम रखना अथवा बदलने की ताकत से है। जब से देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति हावी हुई है, तब से यह जनसंख्या संतुलन के प्रति यह नजरिया और उग्र हुआ है। यह भावना तेजी से गहरा रही है कि किसी विशेष धर्म, जाति अथवा समुदाय की संख्या से ही सियासी शक्ति से अर्जित किया जा सकता है और उस पर पकड़ बनाई रखी जा सकती है।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली ने खुले तौर पर घोषणा कर दी कि राज्य में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। हम यूपी पर राज करेंगे। इसमे सच्चाई कितनी है, यह अलग बात है। लेकिन भावनात्मक स्तर पर यह भी एक तरह का 'जनसंख्या जिहाद' ही है। प्रकारांतर से आबादी को बढ़ाना सत्ता में रहने का रामबाण नुस्खा है। याद करें, उस नारे को जिसमें यह आह्वान किया गया है ' जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी।'

इसका सीधा अर्थ यही है कि न केवल सत्ता बल्कि सामाजिक और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण और वर्चस्व के लिए जरूरी है कि आपकी संख्या अन्य से ज्यादा हो। वरना आप की स्थिति दोयम दर्जे की हो सकती है। संभव है कि आप कहीं भी निर्णायक स्थिति में रहें। ये डर केवल काल्पनिक है, ऐसा भी नहीं है। देश में जहां जहां धार्मिक आधार पर जनसांख्यिकी बदली है, वहां अलगाववाद और विभाजन की दरारें गहराने लगी हैं। और यह केवल भारत में ही नहीं हो रहा है, लोकतंत्र और व्यक्ति और अभिव्यक्त स्वातंत्र्य के घोर समर्थक यूरोपीय देशों में भी हो रहा है।

हालांकि कुछ लोग इसे केवल मिथक मानते हैं, लेकिन देश में बहुसंख्य हिंदुओं की आबादी वृद्धि दर में गिरावट को लेकर आरएसएस के पूर्व सरसंघचालक के.सी. सुदर्शन ने 2000 में ही इस मुद्दे को उठाया था। 8 साल पहले संघ प्रमुख डॉ.मोहन भागवत ने भी कहा था कि बहुसंख्य हिंदुओं की घटती आबादी चिंता का विषय है। उन्होंने युवा दंपतियों से आग्रह किया था कि वो दो से ज्यादा बच्चे पैदा करें। लगभग यही बात हाल में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी ने भी कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में उसी का राज चलता है, जिसकी जितनी ज्यादा संख्या होती है। इसी तरह और भी हिंदू साधु संत इस तरह के आह्वान करते रहते हैं। ऐसी बातों का प्रजनन योग्य युवाओं पर कितना असर होता है, यह स्वतंत्र अध्ययन का विषय है, क्योंकि नेताओं संतो के आग्रह में यह कहीं स्पष्ट नहीं होता कि ज्यादा बच्चे पैदा करने के बाद उनके समुचित पालन पोषण की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए जरूरी संसाधन कहां से आएंगे? बच्चों की अच्छी परिवरिश में होने वाले कष्टों में हिस्सेदारी कौन और कैसे करेगा? या केवल आबादी बढ़ाने के चक्कर में वो ऐहिक जीवन दांव पर लगा दें?

वैसे भी जो नेता, सामाजिक संगठनों के प्रभावी पुरूष और साधु संत ऐसे आह्वान करते रहते हैं, उनका लोगो और खासकर हिंदुओं की आबादी बढ़ाने में निजी स्तर पर कोई खास योगदान नहीं है। या तो वे इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते या फिर अपने संसाधनो को बंटने नहीं देना चाहते। खुद चंद्रबाबू नायडू का एक बेटा है और स्टालिन की सिर्फ दो संतानें हैं। प्रचारक और साधु संतों के परिवार ही नहीं होते। इनमें केवल राजद नेता लालू प्रसाद को अपवाद माना जा सकता है, जिन्होंने अपनी तमाम राजनीतिक सक्रियता के बावजूद परिवार विस्तार के मोर्चे को कमजोर नहीं होने दिया और 9 संतानों के पिता बने। हालांकि लालू ने कभी दूसरों को ऐसा करने की सार्वजनिक सलाह नहीं दी। एक समय था, जब देश की आबादी आज से भी आधी थी और चौतरफा हम दो हमारे दो'का शोर था। कहा जा रहा था कि एक गरीब देश भारी आबादी के बोझ को सह नहीं सकता। लेकिन हमने इतनी तरक्की तो कर ली है कि देश आज 145 करोड़ की आबादी को भी खिला रहा है। तो फिर और आबादी बढ़ाने की बात क्यो की जा रही है? इसके कई पहलू हैं।

पहला तो राजनीतिक है। 2026 में देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों का आबादी के अनुसार नए सिरे से परिसीमन होना है। इसका क्या फॉर्मूला होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर आबादी को ही आधार माना गया तो लोकसभा की वर्तमान सीटें 543 से बढ़कर 888 होने वाली हैं। इनमें सर्वाधिक सीटे सबसे ज्यादा आबादी वाले यूपी में बढ़ेंगी, जो वर्तमान की 80 से बढ़कर 147 हो जाएंगी। इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, पं.बंगाल और मप्र का नंबर है। ये सभी उत्तर और पश्चिमी भारत के राज्य हैं। ऐसे कुल 18 राज्यों में वर्तमान में लोस की फिलहाल 382 सीटें हैं, जो परिसीमन के बाद 688 हो सकती हैं, जबकि दक्षिण के पांच राज्यों में वर्तमान में 129 सीटें हैं, जो बढ़कर 184 ही होंगी। इसी तरह पूर्वोत्तर के राज्यों की सीटों में भी मामूली बढ़ोतरी ही होगी, क्योंकि उनकी आबादी वृद्धि दर बहुत कम है।

तो क्या आबादी का ज्यादा न बढ़ना, खुशहाली की गारंटी भले हो, लेकिन राजनीतिक सत्ता संतुलन में एक नकारात्मक फैक्टर है? दक्षिण के राज्यों का यह सवाल वाजिब है कि अगर उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को काबू में रखकर आर्थिक मोर्चे पर तेजी से तरक्की की तो क्या यह उनका अपराध है, बनिस्बत उन उत्तर और राज्यों के जहां आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन विकास की दौड़ में वो दक्षिणी राज्यों से अभी भी पीछे हैं।

डर ये है कि नए परिसीमन के बाद कम आबादी के कारण केन्द्रीय सत्ता में दक्षिणी राज्यों की भागीदारी कम होती जाएगी, जो एक संघ राज्य के लिए ठीक नहीं होगा। राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में न्यून भागीदारी अलगाववाद की भावना को बढ़ा सकती है और एक राष्ट्र राज्य की अवधारणा इससे खंडित हो सकती है। ये डर इसलिए भी है कि बीजेपी जैसी कोई पार्टी केवल उत्तर पश्चिमी राज्यों से ही इतनी सीटें जीत लेगी कि सत्ता हासिल करने के लिए उसे दक्षिणी राज्यों की जरूरत ही न पड़े। दूसरे, आबादी के असंतुलन का सामाजिक ,सांस्कृतिक और आर्थिक परिणाम भी होगा। न केवल विभिन्न धार्मिक समुदायों में बल्कि खुद हिंदू समाज में भी।

यहां प्रश्न यह भी है कि लोग कितने बच्चे पैदा करें, या न करें, कैसे करें, इसमें सरकारों को दखल देना चाहिए या नहीं? चीन का उदाहरण सामने है। उसे जनसंख्या और लैंगिक असंतुलन के चलते अपनी 35 साल पुरानी 'एक परिवार, एक बच्चा' नीति बदलनी पड़ी और दो बच्चों की अनुमति देनी पड़ी। इसके बाद भी वहां युवा दंपति बच्चे पैदा करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं तो इसके पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। भारत में भी स्थिति काफी कुछ वैसी ही बनती जा रही है, क्योंकि अब बच्चा पैदा करना केवल मर्दानगी अथवा मातृत्व क्षमता का सवाल भर नहीं है, बच्चों की परवरिश कैसे करें, यह प्रश्न भी पहाड़ जैसा है।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदपुराण-परम्पराध्यायः

गतांक से आगे...

यहां व्यासोक्त-अभिमानिनि व्यपदेशस्तु के अनुसार कलशाधिष्ठित चेतन प्रजापति की स्तुति की गई, परन्तु दयानन्द और उनके अनुयायियों ने कः शब्द का अर्थ संस्कृत-टीचरपाठी बालकों की भाँति कौन ही समझ रक्खा है।

कहना न होगा कि यदि इस मन्त्र के प्रजापति देवता का, या द्रोण कलश को प्रार्थना में इसके विनियुक्त होने का, विचार करके भाष्य किया जाता तो पण्डित-समाज में इस तरह की हंसी न होती ।

(2) इसी प्रकार यजुर्वेद के यथेमाँ वाचं आदि मन्त्र से दयानन्दी भाष्य में शुद्र आदि के लिये भी वेद पढ़ने का अधिकार प्रकट किया गया है और ईश्वर को इसका वक्ता ठहरा कर नीचे लिखा अर्थ किया है:-

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। ब्रह्म राजन्याभ्या शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय।। (यजुः 26।2)

[दयानन्दार्थ] परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जने भ्यः) सब मनुष्यों के लिये (इमाम) इस (कल्याणीम) कल्याण अर्थात् संसार और मुक्ति के सुख देने हारी (वाचम) ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का (आवदानि) उपदेश करता हूं।

वैसे तुम भी करो। परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने (ब्रह्मराजन्याभ्याम्) ब्राह्मण क्षत्रिय (आर्याय) वैश्य (शूद्राय) शूद्र और (स्वाय) अपने भृत्य वा स्त्रियादि (अरणाय) और अतिशुद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया है। (सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ 74)

प्रसंग बिगाड़ कर उपर्युक्त अर्थ करने में जो चालाकी की गई है वह उल्टी स्वामी जी के गले का हार हो गई है। केवल वाचम शब्द का अर्थ चारों वेद हो सकता है यह बात कोई पंचम-अन्यथा सिद्ध ही मान सकता है।

क्रमशः...

भारत में पहले आम चुनाव की शुरूआत

अभिनय आकाश

आज से करीब 73 साल पहले 25 अक्टूबर 1951 को भारत में लोकसभा का पहला चुनाव शुरू हुआ। जो लगभग पांच महीनों तक चला था। उस समय भारत के लोगों के लिए आजादी बिल्कुल नई चीजें थी। हमारे पास आजादी का अनुभव केवल चार वर्ष का था लेकिन गुलामी का अनुभव करीब 800 वर्षों का था। कल्पना कीजिए जो देश 800 सालों से गुलाम था वो अचानक आजाद हुआ और इससे पहले वो देश भी नहीं था। देश बना, गणतंत्र बना और फिर वहां अचानक से चुनाव हुए। कहा गया कि ये लोकतंत्र बनेगा। लेकिन किसी ने भी लोकतंत्र को देखा नहीं था जाना नहीं था।

वर्ष 1951 में आजाद भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। वो भारत जो

केवल एक वर्ष पुराना गणतंत्र था, जहां पर 35 करोड़ की आबादी में 85 प्रतिशत लोग अशिक्षित थे। उस समय संचार का कोई माध्यम नहीं था। टीवी नहीं था, रेडियो बहुत कम थे। अखबार बहुत कम थे और कोई माध्यम संचार का ऐसा नहीं था जो लोगों तक पहुंचता हो। लोकतंत्र को लेकर लोगों में जागरूकता न के बराबर थी क्योंकि लोकतंत्र को उन्होंने इससे पहले कभी देखा नहीं था। वहां पर आम चुनाव कराना कितनी बड़ी चुनौती थी।

वोट कैसे डालना है और कहां डालना है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए चुनाव आयोग ने एक फिल्म बनाई। जो देशभर के तीन हजार से ज्यादा सिनेमाघरों में दिखाई गई। लोग मुफ्त में जाकर ये फिल्म देख सकते थे। इसके साथ ही ऑल इंडिया रेडियो पर भी बहुत सारे कार्यक्रम होते थे। जिसमें लोगों को चुनाव प्रक्रिया के बारे में चुनाव के बारे में बताया जाता था। अखबारों में भी लेख और विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को जागरूर किया गया। इस चुनाव में स्टील के कुल मिलाकर 25 लाख बैलेट बॉक्स इस्तेमाल किए गए थे। उस वक्त हर पार्टी का अलग बैलेट बॉक्स होता था। इस चुनाव में 180 टन पेपर का इस्तेमाल हुआ जिसपर उस जमाने में 10 लाख रूपये खर्च हुए थे।

क्या रहा पहले आम चुनाव का परिणाम

देश के पहले आम चुनाव में आजादी की लड़ाई का दूसरा नाम बनी कांग्रेस ने 364 सीटें जीत कर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। देश के पहले आम चुनाव के बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। उनके अलावा 2 ऐसे नेता भी चुनाव जीते जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने, ये थे- गुलजारी लाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री।

क्या बदल रहे हैं चीन और पाक से रिश्ते

रंजीत कुमार

रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच मुलाकात हुई। इस द्विपक्षीय मुलाकात को मुमकिन बनाने के लिए दोनों देशों के दरम्यान अप्रैल 2020 से चल रही सैन्य तनातनी को खत्म करने का पहला अहम कदम उठाया गया है। दोनों नेताओं की मुलाकात पांच साल बाद हुई। कह सकते हैं कि यह रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने की शुरुआत है।

पहला कदम- भारत के लिए यह काफी अहम है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की वैधता स्वीकार करते हुए अपने सैनिकों को पीछे लाने और वहां तक दोनों देशों के सैनिकों द्वारा गश्ती करने के अधिकार को मान लिया है। इस पहले कदम को राजनयिक भाषा में Disengagement की संज्ञा दी गई है। दूसरे कदम के तहत De-escalation और तीसरा कदम De-induction के तौर पर उठाना होगा। इसके बाद ही यह कहना सही रहेगा कि दोनों देश पूर्वी लद्दाख के इलाके में अप्रैल, 2020 के पहले का माहौल वापस ला सके हैं।

भारतीय जमीन पर चीनी सेना के अतिक्रमण की वजह से ही रिश्तों में अभूतपूर्व तनाव पैदा हुआ। पीएम मोदी पिछले पांच बरसों से राष्ट्रपति चिनफिंग से इसलिए नहीं मिले कि चीन जब तक अपनी सेना पीछे नहीं करेगा, तब तक दोनों की मुलाकात नहीं हो सकती। कजान में हुई बातचीत में जिस तरह रिश्तों को सामान्य बनाने पर जोर दिया गया है, उसके मद्देनजर भारत का जोर इस बात पर रहेगा कि

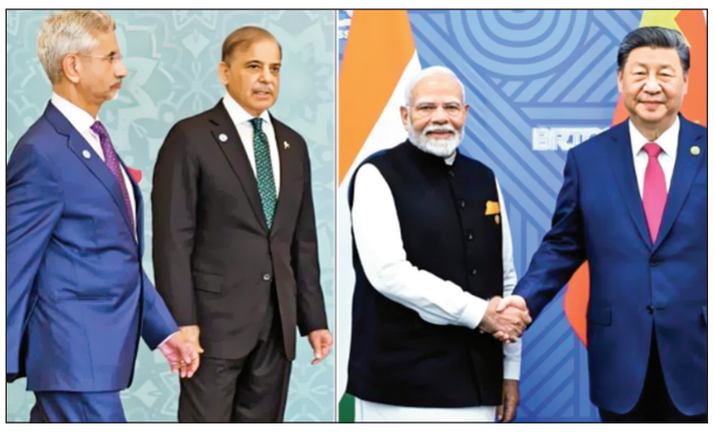

एलएसी के पीछे के इलाकों से दोनों देश अपनी सैन्य तैनाती पूरी तरह खत्म कर दें।

चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख के बर्फीले पर्वतीय सीमांत इलाकों में एलएसी के काफी भीतर तक घुस आए थे। उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच 21 दौर की वार्ता हुई। राजनयिक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्रियों के स्तर पर भी लगभग इतने ही दौर की बात चली। तब जाकर कहीं ताजा सहमति बन पाई है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि देपसांग और डेमचोक पर भी सहमति बनी है।

भारत और चीन के बीच रिश्तों में 2020 के पहले जबरदस्त गर्मजोशी दिखी थी। फिर से उसी गर्मजोशी के लिए थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ठीक ही कहा है कि दोनों देशों को एलएसी पर पूरी तरह परस्पर भरोसे का माहौल कायम करना होगा। इस कड़ी में Disengagement तो ठीक है, लेकिन भारतीय जनमानस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दोनों देशों ने सीमा पर जो 50 हजार सैनिक तैनात कर रखे हैं, उन्हें कब वापस लाया जाएगा? De-escalation की यह प्रक्रिया क्या सर्दियां शुरू होने के पहले हो पाएगी? अगर ऐसा नहीं होता है तो भारतीय सेना पर दबाव बना रहेगा।

चीन ने 2017 के मध्य में भूटान के दावे वाले डोकलाम के इलाके में अपनी सेना भेज दी थी। काफी मान-मनौव्वल और 73 दिनों की सैन्य तैनाती के बाद उसने सैनिक वापस बुलाए थे। इसके बाद, साल 2018 में पीएम मोदी चीन गए थे और वहां शी चिनफिंग के साथ अनौपचारिक शिखर वार्ता शुरू की थी। तब उन्होंने चीनी राष्ट्रपति को भारत आने का न्यौता दिया था। लेकिन इसके तुरंत बाद शी चिनफिंग ने जिस तरह अपनी फौज को पूर्वी लद्दाख के सीमांत इलाकों में भेज दिया वह हैरान करने वाला था।

चीनी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच 1993, 1996, 2005 और 2013 में परस्पर भरोसा पैदा करने वाले समझौतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपनी सेना को भारतीय दावे वाले इलाकों में अतिक्रमण करने का आदेश दिया। इसी का अंजाम रही जून 2020 में गलवान घाटी जैसी घटना। इसके बाद भी भारत के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने बहुत संयम दिखाया। भड़काने वाली परिस्थितियों में भी उन्होंने धैर्य से काम लिया और बातचीत के जरिये ही मामले का हल निकाला।

लेकिन, चिंता कम नहीं हुई है। पिछले साढ़े चार बरसों के दौरान चीनी सेना ने बेहद दुर्गम पर्वतीय इलाकों में पक्के निर्माण कर लिए हैं। आशंका है कि चीन अपने इन सैन्य ढांचागत निर्माण को ध्वस्त कर इलाका पूरी तरह छोड़ देने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पूर्वी लद्दाख के सीमांत इलाकों में सैन्य तनाव और परस्पर अविश्वास की स्थिति बनी रहेगी।

अप्रैल 2020 के बाद चीनी घुसपैठ वाले इलाकों- गलवान, पैंगोंग, गोगरा-हॉटस्प्रिंग से Disengagement के लिए जो सहमति पहले हुई थी, उसके तहत एक अस्थायी बफर जोन बनाया गया था। यह जोन भारत के इलाके में ही बना था। इस इलाके में सैन्य गश्ती की ताजा सहमति हुई है और इसमें यह साफ नहीं कहा गया है कि बफर जोन का क्या होगा। चीन की ओर से सहमति का ऐलान नहीं किया गया, केवल पुष्टि के तौर पर ही कहा गया है कि दोनों देशों के बीच सीमा मसले पर एक हल खोजा गया है। चीन के जवाबी बयान में सैन्य Disengagement का जिक्र नहीं होने से भारतीय सामरिक पर्यवेक्षकों के बीच चीन के इरादों को लेकर शक बना रहेगा, क्योंकि हमारे इस पड़ोसी का भरोसा तोड़ने का पुराना इतिहास रहा है।

आज का इतिहास

1870 अमेरिका में पहली बार पोस्टकार्ड का प्रयोग किया गया।
1875 उनकी सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक, ताचिकोवस्की के पियानो कॉन्सर्टो नंबर 1 का पहला प्रदर्शन, बोस्टन में हंस वॉनबुलो के साथ एकल कलाकार के रूप में दिया गया था।
1917 बोल्शेविक (कम्युनिस्टों) ब्लादिमीर इलिच लेनिन ने रूस में सत्ता हथिया ली।
1920 आयरिश नाटककार और राजनीतिज्ञ टेरेंस मैकस्वीनी की 74 दिनों के बाद ब्रेक्सटन जेल में भूख हड़ताल पर मृत्यु हो गई, जिससे आयरिश संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान में लाया जा सका।
1924 अंग्रेजों ने सुभाषचंद्र बोस को गिरफ्तार करके दो साल के लिए जेल भेज दिया।
1924 ज़िनोविएव पत्र, जिसे बाद में एक जालसाजी के रूप में पाया गया था, डेली मेल प्रकाशित किया गया था, जिससे ब्रिटिश श्रम पार्टी की ब्रिटेन के आम चुनाव में हार को सुनिश्चित करने में मदद मिली।
1935 दो हज़ार से अधिक लोगों की मौत का एक विशाल तूफान और कई बेघर और भूखे हिट हैती को छोड़कर।
1940 बेंजामिन ओ डेविस, सीनियर अमेरिकी सेना के पहले अफ्रीकी-अमेरिकी जनरल बने।
1944 यूएसएस टैंग, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी पनडुब्बी को किसी भी अन्य अमेरिकी पनडुब्बी की तुलना में अधिक जहाजों को वापस लाने का श्रेय दिया गया, जब यह अपने स्वयं के टारपीडो द्वारा डूब गया था।
1944 हेनरिक हिमलर ने एडलवाइस पाइरेट्स, एक गैर-सुधारवादी युवा समूह, जो सेना के रेगिस्तानी और नाज़ियों से सहायता प्राप्त करने वालों की मदद करने का आदेश दिया था।
1945 चीन मित्र राष्ट्रों के लिए जापान के बाद ताइवान के प्रशासन को सफल बनाता है।
1955 पहली बार घरेलू इस्तेमाल के लिए माइक्रोवेव ओवन की ब्रिकी टप्पन नामक कंपनी ने शुरू की।
1960 न्यूयॉर्क में पहली इलेक्ट्रॉनिक कलाई घड़ी बाजार में आई।
1972 पहली महिला एफबीआई एजेंटों को काम पर रखा गया।

बदलते वक्त की मांग है हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने के बारे में सोचना

कमलेश पांडे

राष्ट्रीय राजनीति की अपनी चिंताएं हैं, जबकि सूबाई राजनीति की अपनी दुश्चिंताएं! लोकतांत्रिक सियासत में इनमें तालमेल बिठाना वाकई दुष्कर कार्य है, क्योंकि राष्ट्रीय हितों के ऊपर कहीं साम्प्रदायिक, कहीं जातीय और कहीं क्षेत्रीय हितों को हावी किया जाता रहा है और ऊटपटांग वकालत की जाती रही है। ऐसे में हरेक सिक्के के दो पहलु की तरह ही इन्हें भी लिए जाने की जरूरत है और हमारे समग्र राष्ट्रीय हित कैसे सध सकें, इसके लिए प्राथमिकता तय किये जाने की जरूरत है।

देखा जाए तो भारत में अप्रत्याशित रूप से मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या जहां कुछ राजनीतिक दलों व सामाजिक संस्थाओं के लिए चिंता की बात है और इन्हें नियंत्रित किये जाने की वकालत हिन्दू समुदाय के नेता व समाजसेवी खुलेआम कर रहे हैं और तत्सम्बन्धी डेटा भी सार्वजनिक कर रहे हैं। वहीं, इस बात की वकालत भी की जा रही है कि हिंदुओं को भी बंध्याकरण व नसबंदी की नीति का परित्याग करके ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, ताकि मुस्लिमों के मुकाबले हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा बनी रहे। कमोबेश यही वैश्विक डिमांड भी है। हमारे पास अकूत प्राकृतिक संसाधन हैं, पास-पड़ोस में जनसंख्या के समुचित समायोजन की संभावनाएं हैं और शेष विश्व में बहुत सारे भूभाग आबादी विहीन हैं, जहां रणनीतिक रूप से हिंदुओं को बसाने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे वीर-बांकुडों और समझदार लोगों की मांग यत्र-तत्र-सर्वत्र है। हां, इसके लिए स्पष्ट वैश्विक, राष्ट्रीय और सूबाई सोच होनी चाहिए और सबमें बेहतर तालमेल की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए।

ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी ईसाइयों की है, फिर दूसरी बड़ी आबादी इस्लाम मतावलंबियों की है। जबकि हिन्दू आबादी संसार की तीसरी बड़ी आबादी है। व्यापार में भी इसी तरह से संख्या बल में हिंदू कारोबारी तीसरे पायदान पर हैं। यही वजह है कि हिंदुओं को भी अपनी आबादी मुस्लिमों की तरह बेतहाशा बढ़ानी चाहिए और ईसाई व इस्लाम मतावलंबियों की तरह वैश्विक मतांतरण अभियान दुनिया के हरेक देशों में छेड़ना चाहिए। चूंकि अधिकांश धर्म सनातन मतावलंबियों से ही टूटकर बने हैं, इसलिए घरवापसी अभियान भी चलाया जा सकता है। इसके लिए हिन्दू धर्म को सरल बनाना होगा, ताकि अल्प आय वर्ग के लोग भी इसमें फिट बैठ सकें और मौजूदा आडंबरों की मार उनपर नहीं पड़े। कहना न होगा कि यदि ऐसी रणनीति नहीं अपनाई गई तो निकट भविष्य में अस्तित्व रक्षा के भी लाले पड़ जाएंगे।

इतिहास साक्षी है कि ईसाई व यहूदी धर्म की उत्पत्ति भी इस्लाम धर्म से ही हुई है, इसलिए जब दोनों जुड़वां धार्मिक ताकतें एक हो जाएंगी तो हिंदुओं की वैश्विक परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि का विचार दूरदर्शिता भरा दृष्टिकोण है, यदि सही मायने में देखा जाए तो। इसलिए अब जो दक्षिण भारत से जनसंख्या वृद्धि के सुर सुनाई देने लगे हैं, उससे उत्तर

भारत के लोगों को भी सबक लेनी चाहिए और पारस्परिक तालमेल बिठाकर अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक व लोकतांत्रिक हितों की रक्षा करनी चाहिए।

बता दें कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (आईआईपीएस) द्वारा तैयार इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में बुजुर्गों की आबादी अधिक है। इसे संतुलित करने के लिए ही टीडीपी नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछले हफ्ते कहा था कि लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए कानून लाने की योजना भी बना रही है। राज्य की बुजुर्ग होती आबादी को देखते हुए यह एक नेक कदम है।

इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक पुराने आशीर्वाद का जिक्र करते हुए लोगों को 16 बच्चे पैदा करने की सलाह और शुभकामना दे डाली। इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। समुद्र में फ्लोटिंग हाउस बनाने और ऐसे ही प्राकृतिक जमीन विकसित करने की पूरी गुंजाइश है। बहरहाल, दोनों मुख्यमंत्री यह सलाह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जल्द ही देश में संसदीय सीटों का नये सिरे से परिसीमन होना है। इस परिसीमन के मुताबिक दस लाख लोगों की आबादी पर एक सांसद होगा।

चूंकि दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के मामले में तो बेहतरीन प्रदर्शन कर किया है, जिसकी वजह से वहां प्रजनन दर कम हो गयी है। इसलिए उन्हें अब यह डर सता रहा है कि यदि आबादी के लिहाज से संसदीय सीटों का निर्धारण हुआ तो देश की राष्ट्रीय राजनीति पूरी तरह उत्तर भारत केंद्रित हो जायेगी। लेकिन यदि हिंदुत्व की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के नजरिए से देखा जाए तो दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों का ताजा आह्वान भारत और हिंदुत्व दोनों के लिए बरदान साबित हो सकता है। इसलिए यह कहना कि देश में एक ओर उत्तर भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाये जाने की मांग हो रही है तो दूसरी ओर दक्षिण भारत के दो प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी जनता को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं, में कोई दिक्कत नहीं है। बस, उत्तर भारत के नेताओं को अपना नजरिया बदलना होगा और हिंदुओं की जनसंख्या में अधिकाधिक वृद्धि की रणनीति बनानी होगी। वहीं, मोदी सरकार को भी बदलते नजरिए के मुताबिक विदेश नीति बनानी होगी।

बता दें कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (आईआईपीएस) द्वारा तैयार इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में बुजुर्गों की आबादी अधिक है। रिपोर्ट कहती है कि 2021 और 2036 के बीच इन राज्यों में बुजुर्गों की दर में बहुत अधिक तेजी से वृद्धि होगी। माना जा रहा है कि केरल की जनसंख्या में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 2021 की 16.5त्न से बढ़कर 2036 में 22.8त्न हो जाएगी। वहीं, तमिलनाडु में 13.7त्न से बढ़कर 2036 में 20.8त्न हो जाएगी। उधर, आंध्र प्रदेश में 2021 के 12.3त्न से बढ़कर 2036 में 19त्न हो जाएगी, जबकि कर्नाटक में बुजुर्गों की आबादी 11.5त्न से बढ़कर 2036 में 17.2त्न हो जाएगी और तेलंगाना में 2021 के 11त्न से बढ़कर 2036 में 17.1त्न हो जाएगी।

इसप्रकार मोटे तौर पर यदि देखें तो 15 साल की इस अवधि में जनसंख्या में बुजुर्गों का अनुपात दक्षिण में 6-7त्न बढ़ जाएगा जबकि उत्तर में यह लगभग 3-4त्न होगा। वैसे एक बात गौर करने लायक है कि अधिकांश दक्षिण भारतीय राज्य दुनिया के विकसित देशों की प्रजनन स्तर तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा, भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 2016-19 के लिए एकत्र किए गए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, आंध्र प्रदेश में जीवन प्रत्याशा 69.1 वर्ष, केरल में 71.9 वर्ष और तमिलनाडु में 71.4 वर्ष थी। केवल कर्नाटक की जीवन प्रत्याशा दर राष्ट्रीय औसत से थोड़ी कम यानि 67.9 थी।

वहीं, एक समस्या यह है कि भारत ने अपनी प्रजनन दर बहुत तेजी से कम की है। जहां प्रति महिला छह बच्चों से घटकर दो या एक बच्चे पर आने में फ्रांस को 285 साल लगे, इंग्लैंड को 225 साल लगे, किंतु भारत को इस काम में महज 45 साल लगे। हालांकि, चीन ने इससे भी कम समय में जनसंख्या को नियंत्रित किया, लेकिन वहां ऐसा अत्यंत कठोर और दंडात्मक प्रावधानों के चलते संभव हो सका।

इसके अलावा, दक्षिणी राज्यों की चिंता का बड़ा कारण जल्द ही होने वाला लोकसभा सीटों का परिसीमन भी है। यह कार्य जनगणना के तुरंत बाद होगा। बता दें कि देश में वर्तमान में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएँ जनसंख्या के अनुसार तय की जाती हैं। यदि जन्म दर स्थिर रहती है तो आंध्र प्रदेश में संसद सीटों की संख्या 25 से घटकर 20, कर्नाटक में 28 से 26, केरल में 20 से 14, तमिलनाडु में 39 से 30 और तेलंगाना में 17 से 15 तक हो जाने की उम्मीद है।

वहीं दूसरी ओर, उत्तर के राज्यों की जनसंख्या अधिक होने से उनके निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे उन्हें संसद में बड़ी आवाज मिलेगी। इसके अलावा यदि संसद की सीटें बढ़ाने का फैसला होता है तो भी उत्तरी राज्यों को ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि दक्षिण में जनसंख्या अनुपात के हिसाब से कम सीटें आएंगी। इसलिए भले ही उत्तर-

पिछले 79 वर्षों में कितना बदला है संयुक्त राष्ट्र?

योगेश कुमार गोयल

वर्ष 1945 में दुनिया के 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कर संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया था। दरअसल द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक समतापूर्ण और न्यायोचित बनाने के लिए एक नए संगठन की स्थापना का विचार उभरा था, जो पांच राष्ट्रमंडल सदस्यों तथा आठ यूरोपीय निर्वासित सरकारों द्वारा 12 जून 1941 को लंदन में हस्ताक्षरित अंतर-मैत्री उद्घोषणा में पहली बार सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त हुआ था। उस उद्घोषणा में एक स्वतंत्र विश्व के निर्माण हेतु कार्य करने का आह्वान किया गया था, जिसमें लोग शांति और सुरक्षा के साथ भयमुक्त वातावरण में रह सकें तथा निजीकरण एवं आर्थिक सहयोग के मार्ग की खोज कर सकें।

उसके बाद 1944 में सोवियत संघ, अमेरिका, चीन तथा ब्रिटेन के प्रतिनिधियों द्वारा वॉशिंगटन के डम्बर्टन ओक्स एस्टेट में कई बैठकों के बाद एक शांतिरक्षक वैश्विक संस्था बनाने की रूपरेखा तैयार की गई, जिसके आधार पर 50 देशों के प्रतिनिधियों के बीच 1945 में बातचीत हुई और 26 जून 1945 को सभी 50 देशों द्वारा चार्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद यह चार्टर 24 अक्तूबर 1945 से प्रभावी हो गया।

तभी से प्रतिवर्ष 24 अक्तूबर को 'संयुक्त राष्ट्र दिवस' मनाया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से ही दुनिया के अनेक देश इसके साथ

जुड़ते गए और 50 सदस्यों के साथ शुरू हुए इस वैश्विक संघ के सदस्य देशों की संख्या अब 193 हो चुकी संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश थे अमेरिका, फ्रांस, रूस तथा यूनाइटेड किंगडम, जिनकी द्वितीय विश्वयुद्ध में अहम भूमिका थी। हालांकि विडम्बना है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के इन 79 वर्षों में यह वैश्विक संस्था अब धीरे-धीरे अपनी प्रासंगिकता खोने लगी है।

दरअसल बीते 79 वर्षों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था, हथियार, मीडिया, समाज, मुद्रा तथा समाज से संबंधित तमाम नीतियां इसके पांच स्थायी सदस्य देशों ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, रूस तथा फ्रांस के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही निर्धारित की जाती रही हैं।

ऐसी नीतियों का खामियाजा भारत के अलावा जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों को भुगतना पड़ा है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थायी सदस्यता के लिए तमाम मानदंडों को पूरा करने के बाद भी दशकों से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिए प्रयासरत है।

कोटा और जाति के मुद्दे फिर राजनीति में छाने लगे

पूनम आई. कौशिश

कोटा और जाति भारत में चुनावों में सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं और ये मुद्दे फिर राजनीतिक क्षितिज पर छाने लगे हैं। राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को तुष्ट करने के लिए आरक्षण को मूंगफलियों की तरह बांट रहे हैं। यह इस बात को रेखांकित करता है कि 21वीं सदी का भारत भी जस का तस बना हुआ है। पिछले सप्ताह भाजपा सरकार का हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने अगस्त में उच्चतम न्यायालय की 7 सदस्यीय खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय को लागू किया। इस निर्णय में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के उप वर्गीकरण की अनुमति दी गई थी।

इस प्रकार अनुसूचित जातियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। वंचित अनुसूचित जातियां, जिसमें वाल्मीकि, धनका, मजहबी सिख, खटीक जैसे 36 समूह हैं और अन्य अनुसूचित जनजातियां, जिसमें चमार, जटिया चमार, रहगर, रैगार, रामदासी, रविदासी और जाटव शामिल हैं और एक समूह को राज्य में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत कोटा का आधा कोटा मिलेगा। इसका मूल उद्देश्य एक बड़े समूह के अंतर्गत असमानता को दूर करना है, जो एक ध्रुवीकरण का मुद्दा बन गया है क्योंकि शक्तिशाली दलित समूह इसका विरोध कर रहे हैं। यह भाजपा द्वारा इस समुदाय के अंतर्गत मतभेदों को भुनाने का प्रयास भी है क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से अनुसूचित जातियां भाजपा विरोधी दलों का समर्थन करती रही हैं और अब भाजपा उनका वोट प्राप्त करने का प्रयास कर रही है।

इस बार के चुनाव में 17 आरक्षित सीटों में से भाजपा ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है जो 2019 से 5 सीटें अधिक हैं। यही नहीं, अन्य पिछड़े वर्गों को वर्चस्ववादी और गैर-वर्चस्ववादी वर्गों में बांटने के बाद पार्टी अब अनुसूचित जातियों के वोटों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना-शिंदे और राकांपा-अजीत की महायुति

सरकार भी चुनावों के लिए तैयार है और उसने भी अनुसूचित जातियों के कोटे को उपजातियों में वर्गीकृत करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

दलितों का उपवर्गीकरण पहली बार किया जाएगा, किंतु आज दलित शक्तिशाली वर्ग बन गया है और यह इसके अंतर्गत दलितों को एकजुट करने के पैटर्न को बदल देगा। व्यापक दृष्टि से देखें तो उपवर्गीकरण एक सकारात्मक कदम है क्योंकि दलितों में संपन्न वर्ग आरक्षण का अधिक लाभ उठा रहे हैं और हाशिए पर तथा सीमान्त वर्ग इससे वंचित रह रहे हैं। अनुसूचित जातियों की श्रेणियां बढ़ रही हैं और इस श्रेणी में नए समूहों को जोड़ा जा रहा है, इसलिए सीमान्त समूहों को रोजगार, शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि मिलने के बेहतर आसार हैं। यदि उपवर्गीकरण को कुशलता और ईमानदारी से किया जाए तो आरक्षण अधिक समावेशी बनेगा क्योंकि इसमें उन वर्गों की पहचान होगी जो सबसे ज्यादा वंचित हैं। पंजाब में अनुसूचित जातियों की संख्या 32 प्रतिशत है और उसने 1975 में इनके आरक्षण में उपवर्गीकरण की आवश्यकता को महसूस किया तथा वाल्मीकि तथा मजहबी सिखों के लिए अनुसूचित जातियों के आरक्षण का 50 प्रतिशत आरक्षित किया। तमिलनाडु में भी सामाजिक न्याय के लिए ऐसा किया गया। निस्संदेह सामाजिक न्याय एक वांछनीय और प्रशंसनीय लक्ष्य है और साथ ही सरकार का उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना, सबको समान अवसर तथा जीवन की बेहतर गुणवत्ता उपलब्ध कराना है। आरक्षण दशकों से सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा उपलब्ध न करा पाने का प्रतिस्थापन बन गया है, परिणामस्वरूप अदूरदर्शिता से आरक्षण का विस्तार किया गया, जिसके चलते विभिन्न समूहों में संकीर्ण पहचान मुखर हुई और स्थिति यहां तक बन गई कि चुनावी सत्ता की राजनीति में संख्या की दृष्टि से बड़े समूह अन्य समूहों की कीमत पर लाभ उठा रहे हैं।

सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, जिसके चलते जातीय प्रमाण पत्र घोटाले भी सामने आए हैं। यह बताता है कि हमारी नीति किस तरह विफल रही है क्योंकि आरक्षण लोगों के उत्थान या उनके जीवन को बेहतर बनाने का एकमात्र उपाय नहीं है। 90 के दशक से राजनीतिक दलों ने आरक्षण का उपयोग छोटे समूहों को आकर्षित करने के लिए किया है क्योंकि अब दलित वोट एक जैसे नहीं पड़ते और इससे एक नई राजनीतिक स्थिति बनी है। आगे स्थिति में सुधार इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अनुसूचित जातियों में असमानता को स्वीकार करें, उसका निराकरण करें और जमीनी स्तर पर इसे दूर करने का प्रयास करें। सच्चाई यह है कि आज हम एक दुष्चक्र में फंसे हुए हैं और जिसे हर कीमत पर सत्ता प्राप्त करने के लिए लालायित तुच्छ नेताओं ने और जटिल बना दिया है। यही नहीं, इसमें वर्ग संघर्ष का खतरा भी पैदा हो गया है। हमारे नेताओं और उनके चेलों को समझना होगा कि सामाजिक न्याय और समान अवसर कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार नहीं है। जाति आधारित आरक्षण विभाजनकारी रहा है और इसका प्रयोजन पूरा नहीं हुआ। हमारे राजनेताओं को यह भी समझना होगा कि वे आज की जैनरेशन भीड़भाड़ भरे रोजगार बाजार में गुणवत्ता के आधार पर नौकरी चाहती है। केवल शिक्षा और रोजगार में आरक्षण से उत्कृष्टता नहीं आएगी। इसके लिए इन वर्गों को प्रशिक्षित करने के लिए नए तरीके विकसित करने होंगे ताकि वे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

कश्मीर में ध्वस्त हो आतंकियों का नेटवर्क

डॉ. अमित सिंह

कश्मीर के सोनमर्ग के नजदीक श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सुरंग निर्माण की जगह पर रविवार को हुए आतंकी हमले में सात लोगों की मौत बेहद दुखद है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब आतंकियों ने किसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की जगह को निशाना बनाया है। उससे पहले एक अन्य घटना में एक कामगार की हत्या भी हुई है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का इतिहास कई दशक पुराना है, लेकिन 2019 में अनुच्छेद 370 में संशोधन करने और मोदी सरकार द्वारा कड़ा रवैया अपनाये जाने से आतंकवाद को बहुत हद तक नियंत्रित किया गया है। उल्लेखनीय है कि दो बार नियंत्रण रेखा के पार भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकी गिरोहों को भारी झटका दिया है। इन कारणों से पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकी समूहों में बड़ी बेचैनी रही है।

हमने देखा है कि कुछ समय पहले जब घाटी में उनके नेटवर्क को लगभग समाप्त कर दिया गया और चौकसी पुख्ता कर दी गयी, तो उन्होंने जम्मू क्षेत्र में हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। भारतीय सुरक्षाबलों ने कड़ाई से इन चुनौतियों का मुकाबला किया है और अभी भी जम्मू क्षेत्र में आतंकियों के सफाये की कोशिश जारी है। ऐसे में लगता है कि आतंकवादी कश्मीर में भी कायराना हमलों को अंजाम देने की रणनीति अपना रहे हैं। हाल में जम्मू-कश्मीर में संपन्न हुए लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने उत्साहपूर्ण भागीदारी की है। अभी वहां नयी सरकार का गठन भी हुआ है। इससे भी आतंकी समूहों और उनके पाकिस्तानी प्रायोजकों की छाती पर सांप लोट रहे हैं। वे घाटी में फिर से दहशत का माहौल बनाकर लोगों के भरोसे को डगमगाने की फिराक में हैं। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की नयी सरकार बनी है, उसे जनता का भारी समर्थन प्राप्त है। जम्मू क्षेत्र में भाजपा को अच्छी-खासी सीटें हासिल हुई हैं।

सरकार गठन में उमर अब्दुल्ला ने संतुलन बनाने की कोशिश की है और जम्मू क्षेत्र से मंत्रिमंडल में कई मंत्री शामिल किये गये हैं। कुछ ऐसे मंत्री भी हैं, जिनकी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भाजपा से संबद्ध रही है। बार-बार उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि घाटी से विस्थापित

कश्मीरी पंडितों की वापसी हो तथा उस क्षेत्र में विकास को गति दी जाए। हालांकि चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि वे पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ विशेष राज्य की स्थिति बहाल करने की कोशिश करेंगे, पर कैबिनेट की पहली बैठक में केवल पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को ही पारित किया गया है। वे यह भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंध रखते हुए प्रदेश की भलाई और बेहतरी के काम किये जाएं। उन्होंने अनेक कार्यक्रमों के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा भी की है।

ऐसे में मेरा मानना है कि वर्तमान स्थिति को आतंकी अपने गले के नीचे नहीं उतार पा रहे हैं। वे चाहते हैं कि घाटी में अस्थिरता का वातावरण बने, इसीलिए आतंकी हमलों का सहारा लिया जा रहा है। रविवार का हमला निश्चित रूप से एक बड़ा हमला है और यह सोच-समझ कर किया गया है। ऐसे हमले आगे न हों और आतंकियों का मनोबल न बढ़े, इसके लिए उनके ठिकानों एवं नेटवर्क को निशाना बनाना जरूरी हो गया है। यदि आवश्यक हो, तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयों पर भी विचार किया जाना चाहिए। पहले हुए ऐसे स्ट्राइक के बाद आतंकियों की क्षमता में बड़ी कमी आयी थी। बीते कुछ समय में पाकिस्तान के भीतर अनेक आतंकी सरगनाओं की हत्या अज्ञात लोगों ने की है। इससे भी उनके गिरोहों को झटका लगा है। अतीत के अनुभवों और दुनिया के विभिन्न उदाहरणों को सामने रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को अपनी रणनीति की समीक्षा कर नये सिरे से कार्रवाइयों पर विचार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसमें देरी करने से आतंकियों को दहशत फैलाने के लिए ज्यादा वक्त मिल सकता है। जम्मू-कश्मीर के सभी दुश्मन गिरोहों को निशाने पर लेने की जरूरत है।

दिल्ली में हुए विस्फोट के बारे में भी संदेह जताया जा रहा है कि इसके पीछे भारत-विरोधी आतंकी समूहों का हाथ हो सकता है। हमने देखा है कि पश्चिमी देशों से अपनी गतिविधियां चला रहे खालिस्तानी समूह भारत को धमकियां देते रहते हैं। इसी प्रकार विमानों में बम की झूठी धमकियों से देश को परेशान करने की कोशिश हो रही है। इस परिदृश्य में आतंकवाद के विरुद्ध निष्ठुर होकर कार्रवाई होनी चाहिए। बीते दिनों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की यात्रा की और वहां के विदेश मंत्री से उनकी अनौपचारिक बातचीत हुई। यह यात्रा शंघाई सहयोग संगठन की सालाना बैठक के संदर्भ में थी। दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत से ऐसी उम्मीदों को बल मिला है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार का दौर शुरू हो सकता है। हालांकि यह उम्मीद रखते हुए यह भी कहा जाना चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसे समूह हैं, जो दोनों देशों के संबंधों को सामान्य नहीं होने देना चाहते हैं। आतंकी समूह बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि दोनों देशों में बातचीत हो, व्यापार बढ़े और लोगों के बीच संपर्क बने। इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं।

जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मित्रता का संदेश लेकर बस से लाहौर गये थे, तब ऐसा लगा था कि द्विपक्षीय संबंधों का एक सकारात्मक अध्याय प्रारंभ होगा। लेकिन उसके बाद कारगिल में घुसपैठ कर पाकिस्तानी सेना ने युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काबुल से लौटते हुए अचानक पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर पहुंच गये थे, तब भी ऐसी आशाओं को बल मिला था कि अतीत की घटनाओं को पीछे छोड़ दोनों देश भविष्य की ओर सकारात्मकता से बढ़ेंगे। लेकिन उस यात्रा के बाद पठानकोट में बड़ा आतंकी हमला हो गया। अब जयशंकर की यात्रा से उम्मीद बंधी है, तो रविवार की घटना हो गयी। पाकिस्तान में जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, जो शांति की विरोधी हैं, वे संबंधों में सुधार की भी विरोधी हैं। मुझे लगता है कि परस्पर संबंधों को तनावपूर्ण बनाये रखने के लिए भी आतंकी हमलों जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है।

पंचायतें ही भारत के लोकतंत्र का आधार

मोहन लाल

यही सत्य है, यही लोकतंत्र है कि ग्राम-पंचायतों के चुनाव निष्पक्ष हों और राजनीति को पंचायती चुनावों से अलग रखा जाए। यदि केंद्र सरकार सचमुच लोकतंत्र हितकारी है तो उसे प्रत्येक गांव तक अपना अस्तित्व दिखाना पड़ेगा और हर वयस्क जो गांव में रहता है, उस तक सच्चे लोकतंत्र को ले जाना होगा। आजादी के इतने वर्षों के बीत जाने पर भी हमारे गांव उपेक्षित, वंचित और गरीबी रेखा से नीचे स्तर का जीवन जी रहे हैं। सरकारों को बापू गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू के 'ग्राम स्वराज' के सपनों को पूरा करना होगा। विनोबा भावे और जय प्रकाश के 'ग्राम चलो' नारे को साकार करना होगा। लोकतंत्र के आधार को गांव तक पहुंचाना होगा। आज पंडित जवाहर लाल नेहरू का वह भाषण याद आ रहा है, जो उन्होंने पंजाब के राजपुरा (पटियाला) में 1960 को दिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि नया भारत तीन क्रांतियों की ओर अग्रसर है। पहली क्रांति भारत में शिक्षा का प्रसार, दूसरी क्रांति कृषि सुधार, तीसरी क्रांति 'पंचायती राज'। तीनों क्रांतियां भारत के लोकतंत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगी। देहात के दबे-कुचले लोगों को अपना राज मिलेगा। उन्हें अपना शासन आप चलाना आएगा। लोकतंत्र के प्रति गांव के लोगों का विश्वास बनेगा। परन्तु नेहरू के बाद की केंद्र सरकारों ने नेहरू के प्रगतिशील नारों से मुंह ही मोड़ लिया। दोस्तो, आपको नहीं लगता कि पंचायती चुनावों ने देहात के लोगों का जीवन बदल दिया। उन्हें अपना राज आप संभालने की आदत आने लगी। अब तो सरकारों ने महिलाओं के लिए पंचायत चुनाव में 33 प्रतिशत आरक्षण भी लागू कर दिया है। दलित, अनुसूचित और वंचित समाज के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है। पढ़ी-लिखी युवा पंच-सरपंच महिलाएं तो अपने-अपने गांवों को 'माडल ग्राम' बनाने में लग जाएंगी। चुने गए पंच-सरपंच अब जात-बिरादरी के झगड़ों को छोड़ भारत के लोकतंत्र का आनंद उठाएंगे। पंच-सरपंच गांव के विकास की राह को आसान बनाते चलेंगे। पंच-सरपंच याद रखें कि पंजाब में पंचायती चुनाव 10 साल बाद हुए हैं। पांच साल की ग्राम विकास योजनाएं बनाकर आगे बढ़ते चलें। अब जात-पात के बंधनों से अपने को मुक्त करो। भारत के लोकतंत्र को और मजबूती दो। गांव के विकास के लिए राजनेताओं पर निर्भर न रहो। राजनीति छोड़ अपने गांव के भाग्य विधाता बनें, यही तुम्हारे और तुम्हारे गांव के हित में होगा। असल स्थानीय सरकार तो पंचायत ही है। ग्राम पंचायत क्षेत्र, जनसंख्या और वित्तीय साधन जुटाने में सबसे छोटी और सबसे कारगर इकाई है। बलवंत राय कमेटी का सुझाव था कि शासन का विकेंद्रीकरण किया जाए। केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार, फिर जिला सरकार, फिर तहसील स्तर पर सरकार फिर ब्लाक समिति सरकार और फिर सबसे नीचे पंचायत सरकार। यह है सत्ता का विकेंद्रीकरण। ग्राम पंचायत अंतिम सरकार है। उद्देश्य सरकारों का बस इतना कि अंतिम व्यक्ति भी सत्ता में भागीदार बने। दलित, प्रताड़ित, घोर गरीब, वंचित तक सरकारी पहुंच हो जाए। पंचायती राज स्वशासन (यानी अपना शासन) की ओर पहला ठोस कदम है। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायत के संगठन, कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन किया गया है। भारत में इस समय 2,25,832 से अधिक पंचायतें हैं। पंजाब में 200 आबादी वाले, हरियाणा में 500 आबादी वाले, हिमाचल में 1000 आबादी वाले गांवों को पंचायत माना जाता है। यदि किसी गांव की आबादी इससे कम हो तो अन्य गांवों को जोड़ कर पंचायत बना दी जाती है। गांव पंचायत का आकार इसकी सदस्यता के अनुसार 5 से 31 तक बनाया जाता है। हरियाणा में 6 से 20 तक, पंजाब व हिमाचल प्रदेश में 5 से 13 तक, उत्तर प्रदेश में 16 से 31 तक सदस्य संख्या रखी जा सकती है। पंचायतों के चुनाव ग्राम सभा गुप्त मतदान द्वारा करवाती है। प्रत्येक वोटर को दो वोट डालने पड़ते हैं। एक सरपंची के लिए और दूसरा वोट पंच के लिए। कई पंचायतें मिल-बैठ कर सर्वसम्मति से पंचों और सरपंच का चुनाव कर लेती हैं। राज्य सरकार किसी भी वैधानिक ढंग से चुनी हुई पंचायत को भंग नहीं कर सकती।

गुलाबी ठंड में दक्षिण भारत के इन जगहों को एक्सप्लोर करें, रोमांच से भरपूर होगी यात्रा

दिवाली के बाद से सर्दियां लगभग शुरु हो जाती हैं और सर्दी का एहसास भी अब महसूस होने लगा है। इस दौरान घूमने का एक अलग ही मजा होता है। अगर आप भी घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आप साउथ इंडिया के इन जगहों पर जरुर जाएं। शुरुआती सर्दी के मौसम में कई लोग बर्फ से ढके पहाड़ देखने जरुर जाते हैं। लेकिन आप गुलाबी ठंड में दक्षिण भारत की सुखद एहसास ले सकते हैं। अगर आप सर्दियों की ठंडी हवा से बचना चाहते हैं, तो आप इन जगहों पर घूमने जरुर जाएं।

प्राकृतिक सौंदर्य

कोलाड का प्राकृतिक दृश्य मनमोहक है। यहाँ की हरियाली, पहाड़ियाँ और झरने इसे एक खूबसूरत पर्यटन स्थल बनाते हैं। खासकर मानसून के दौरान, जब यहाँ की नदियाँ और झरने पूरी तरह से भर जाते हैं, तब इस स्थान की सुंदरता देखते ही बनती है। कोलाड के आस-पास के हरे-भरे जंगल और घाटियाँ पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं।

प्रमुख आकर्षण

रिवर राफ्टिंग- कोलाड की मुख्य आकर्षणों में से एक है यहाँ की कर्जन नदी पर रिवर राफ्टिंग। यह गतिविधि साहसिक प्रेमियों के लिए एक अद्वितीय अनुभव है। यहाँ की जलधारा की वेग के साथ राफ्टिंग करना एक रोमांचकारी अनुभव होता है।

दिवेघर और भिरवाडी झरना

ये झरने मानसून में पूरी तरह से बहते हैं और उनका दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है। यहाँ पर आप पिकनिक मना सकते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं।

कूर्ग

इस लिस्ट में अगला स्थान कूर्ग का है, जो भारत के स्कॉटलैंड के नाम से मशहूर है। यह समृद्ध संस्कृति, सुंदर दृश्यों, झरनों, रोमांच और आश्चर्यजनक कॉफी बागानों का के लिए जाना जाता है।

यहां का मुख्य पर्यटक आकर्षण तमारा कार्निवल, मदिकेरी किला, एबी और इरुप्पु फॉल्स और होन्नमाना केरे झील हैं। कूर्ग की एक राउंड ट्रिप के लिए आपको ऊटी जितना ही खर्च करना पड़ सकता है।

वायनाड

इस लिस्ट में अगला स्थान केरल का वायनाड है। हरी-भरी हरियाली, वन्य जीव और धुंध भरा मौसम, यह जगह सर्दियों में घूमने के लिए एकदम बढ़िया है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। यहां के टॉप पर्यटक आकर्षण एडक्कल गुफाएं, चेम्बरा पीक, कुरुवा द्वीप और करापुझा बांध हैं। वायनाड की 3 से 4 दिन की यात्रा का खर्च पैकेज के आधार पर प्रति व्यक्ति 30,000 रुपये से 40,000 रुपये हो सकता है।

सर्दियों के मौसम में अगर आप कहीं घूमने की सोच रहे हैं, तो आप साउथ इंडिया के इन जगहों पर घूमने के लिए जरुर जाएं। इन जगहों पर सुहावना मौसम, सुंदर दृश्य, ठंडी हवा और कई सुंदर चाय बागान देखने को मिलते हैं। आप गुलाबी ठंड में दक्षिण भारत की सुखद एहसास ले सकते हैं।

ऊटी

तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में नीलगिरि पहाड़ियों में स्थित, ऊटी दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहां सुहावना मौसम, सुंदर दृश्य, ठंडी हवा और कई सुंदर चाय बागान देखने को मिलते हैं। इसके अलावा, प्रकृति के बीच एक टॉय ट्रेन की सवारी उन लोगों के लिए एकदम सही है जो एक आरामदायक छुट्टी की तलाश में हैं। दिल्ली से ऊटी की 4-5 दिन की यात्रा में आपके बजट के आधार पर प्रति व्यक्ति लगभग 35,000 रुपये - 45,000 रुपये का खर्च आ सकता है। ऊटी में इन बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है। सर्कस, कुछ कुछ होता है और गोलमाल अगेन जैसी फिल्मों की शूटिंग ऊटी में हुई थी।

अलेप्पी

अलेप्पी भारत के केरल में सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। वेनिस के रूप में लोकप्रिय यह गंतव्य बैकवाटर, हरे-भरे दृश्य और सुंदर समुद्र तटों का घर है। यह स्थान एक रोमांटिक माहौल प्रदान करता है और यह जगह उन लोगों के लिए आदर्श है जो अपने सहयोगियों के साथ कुछ खास समय बिताना चाहते हैं। यहां के प्रमुख आकर्षण अलाप्पुझा और मरारी बीच, पुन्नमदा झील पर हाउस बोटिंग और कुमारकोम पक्षी अभयारण्य हैं। यहां एक राउंड ट्रिप के लिए आपके पैकेज के अनुसार प्रति व्यक्ति 40,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का खर्च आ सकता है।

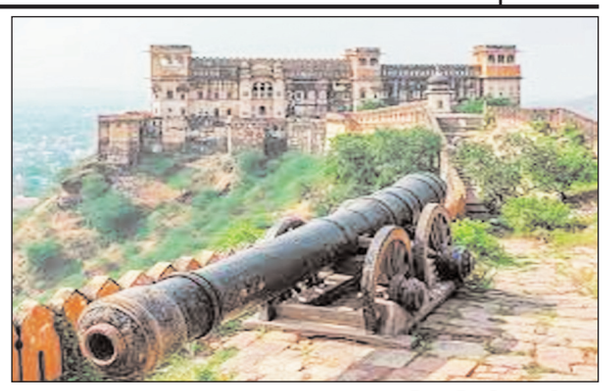

जयपुर में अब तक ये एडवेंचर एक्टिविटी नहीं की तो क्या ही किया, ऐतिहासिक किले देखने के बाद इन 3 जगहों पर जाएं

पिंक सिटी के नाम से मशहूर राजस्थान का जयपुर शहर ऐतिहासिक दृष्टि और शाही इतिहास के लिए जाना जाता है। जयपुर, भारत के सबसे आकर्षक और सांस्कृतिक जगहों में से एक है। यहां पर आप ऐतिहासिक किलों, महलों और रंग-बिरंगी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर देश-विदेश से कई पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। जयपुर में आपको हर जगह विदेशी पर्यटक देखने को मिल जाएंगे। जयपुर मे् किले और महल जैसे आमरे किला, नाहरगढ़ किला और सिटी पैलेस जैसी जगहों के लिए फेमस है। अगर आप जयपुर जा रहे हैं तो किले देखने के बाद एडवेंचर एक्टिविटी जरुर कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको इन जगहों के बारे मे बताने जा रहे हैं।

जयपुर में पैराग्लाइडिंग करें

जयपुर में किले और महल देखकर आप भी काफी ऊब गए होंगे। यदि आप रोमांचक पलों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप पैराग्लाइडिंग जरुर कर सकते हैं। जयपुर की ऊंची पहाड़ियों और खुली जगहों के कारण यह एक्टिविटी और भी मजेदार हो जाती है। पैराग्लाइडिंद करते हुए आप सुंदर शहर का नजारा देख सकेंगे। एडवेंचर लवर के लिए यह एक्टिवटी बेहद खास लगेगी।

- 500-700 फीट की ऊंचाई पर आप यात्रा कर सकते हैं।
- इसके साथ ही इसमें 10 से 70 वर्ष तक के लोग यात्रा कर सकते हैं।
- समय - प्रात: 06ः00 बजे से प्रात: 10ः00 बजे तक
- शाम का समय प्रात: 03ः00 बजे से सायं 07ः00 बजे तक

हॉट एयर बैलून राइड

अगर आप जयपुर में हॉट एयर बैलून राइड का मजा लेना चाहते हैं तो आप आमेर किला और जल महल जा सकते हैं। यहां सुंदर नजारों के साथ-साथ आप सुंदर तस्वीरें ले सकते हैं। आपको बता दें कि, हॉट एयर बैलून को उड़ाने वाला पायलट भी आपके साथ ही रहेगा। वहीं, मौसम खराब के दौरान बैलून राइड नहीं कराई जाएगी।

- हॉट एयर बैलून की पैकेज फीस- प्रति व्यक्ति 11,499 रुपये
- तीन व्यक्ति के साथ यात्रा करने पर कुल 43,000 रुपये देने होंगे।
- एक बच्चे के लिए 1 घंटे की सवारी 7000 रुपये में होती है।
- अप्रैल से जून तक सवारी सुबह 5ः30 बजे शुरू होती है।
- सितम्बर से मार्च तक आप सवारी सुबह 6ः45 बजे और शाम 4ः00 बजे ले सकते हैं।

स्लीप टूरिज्म के लिए बेहद हसीन हैं भारत की ये जगहें, एक बार आप भी जाएं घूमने

हनीमून ट्रिप प्लान करने से पहले एक बार जरूर देख लें ये टूर पैकेज

अक्सर कपल्स हनीमून के लिए अच्छी जगह की तलाश करते हैं। बता दें कि कपल्स के लिए टूर पैकेज से यात्रा करना अच्छा होता है। क्योंकि इस दौरान कपल्स को ट्रिप की योजना बनाने की टेंशन नहीं होती है। टूर पैकेज में यात्रा का पूरा शेड्यूल पहले से तय होता है। इसमें बस-कैब की सेवाएं शामिल होती है।

वहीं इस पैकेज में ट्रांसपोर्टेशन और होटल की बुकिंग भी पहले से हो जाती है। जिसकी वजह से ट्रिप के दौरान कपल्स को परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ता है। बस आपको इस टूर पैकेज का टिकट बुक करना पड़ेगा। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको टूर पैकेज से जुड़ी सभी जानकारी देने जा रहे हैं।

गंगटोक, दार्जिलिंग और न्यू जलपाईगुड़ी

इस टूर पैकेज में आपको एक साथ तीन जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा।
इस पैकेज में सुविधाओं को देखने के बाद ही टिकट बुक करें।
बता दें कि 30 नवंबर को कोलकाता से इस टूर पैकेज की शुरूआत होगी।
यह टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का है।
इस दौरान आपको ट्रेन से यात्रा करने का मौका मिलेगा।
इस पैकेज में 2 लोगों के साथ यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति 37,550 रुपए फीस देनी होगी।
इस पैकेज फीस में स्टे, खाना और घूमने के लिए बस और ट्रेन टिकट का खर्च भी शामिल है।
आप भारतीय रेल की ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट बुकिंग का तरीका आसान है।
गुवाहाटी, शिलांग, चेरापूंजी, मावलिनोंग और काजीरंगा
इस टूर पैकेज में आपको एक साल 5 जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा।
इस पैकेज की शुरूआत 03 दिसंबर से चंडीगढ़ से हो रही है।
यह पैकेज 6 रात और 7 दिन का है।
इस दौरान आपको फ्लाइट से यात्रा करने का मौका मिलेगा।
इस टूर के दौरान 2 लोगों के यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति 48,860 रुपए देने होंगे।

चंडीगढ़, कुफरी और शिमला

इस टूर पैकेज में आपको एक साथ 2 जगहों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा।
इस पैकेज की शुरूआत 04 अक्तूबर से कोलकाता से हो रही है।
यह पैकेज 5 रात और 6 दिन का है।
इस दौरान आपको ट्रेन से यात्रा करने का मौका मिलेगा।
बता दें कि 2 लोगों के साथ यात्रा करने पर आपको प्रति व्यक्ति रुपए चुकाने होंगे।
इस टूर पैकेज में मिलने वाली सुविधाओं को देखने के बाद ही टिकट बुक करें।

घूमने जाएं दक्षिण भारत

दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल औक अन्य् राज्य कई फेमस जगहें हैं। जहां पर स्लीप टूरिज्म के लिए आप जा सकते हैं। साउथ की मैसूर, कुर्ग और मुन्नार जैसी कई हसीन जगहें हैं।

जो जगहें हरियाली से घिरी हुई हैं। यहां पर बादलों की चादर में हरे-भरे पहाड़ों के बीच घूमने और नींद लेने से तनाव दूर होता है। कुर्ग में आपको कई ऐसे रिजॉर्ट मिलेंगे, जहां पर लोग आयुर्वेदिक उपचार और मेडिटेशन की सुविधाएं दी जाती हैं। स्लीप टूरिज्म के लिए यह जगहें बेस्ट साबित हो सकती हैं।

जरूर जाएं ऋषिकेश

सस्ती ट्रिप के लिए ऋषिकेष बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि यहां पर रुकना, खाना और घूमना अन्य जगहों के मुकाबले काफी सस्ता है। इस शहर को भारत की योगनगरी भी कहा जाता है। यहां पर देश-विदेश से लाखों की संख्या में टूरिस्ट मेडिटेशन और योग के लिए यहां आते हैं। ऐसे में ऋषिकेष स्लीप टूरिज्म के लिए काफी अच्छी जगह है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता के बीच नींद लेना आपके दिमाग को शांत रखने में मदद करता है।

आज हम आपको इस अनोखे टूरिज्म के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत में कई ऐसी जगहें मौजूद हैं, जहां पर आप स्लीप टूरिज्म को एंजॉय करते हुए मेंटल स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में। घूमना-फिरना आखिर किसी पसंद नहीं होता है। अक्सर लोग वीकेंड पर घूमने का प्लान बनाते हैं। वहीं जिंदगी में चल रही स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम अक्सर अच्छी जगहों का दीदार करना पसंद करते हैं। कई रिसर्च बताते हैं कि नई और खूबसूरत जगहों का दीदार करने से मानसिक तनाव कम होता है। हालांकि भारत में आजकल ट्रैवलिंग के कई मॉर्डन तरीके आजमाएं जा रहे हैं। जिनमें से एक स्लीप टूरिज्म भी है। मिस यूनिवर्स के स्टेज पर हुई ये अजीब घटना कोई भूल नहीं पाएगाऔर जानें स्लीप टूरिज्म, इसके नाम से ही पता चलता है कि इस ट्रिप में नींद लेने की बात हो रही है। आज हम आपको इस अनोखे टूरिज्म के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत में कई ऐसी जगहें मौजूद हैं, जहां पर आप स्लीप टूरिज्म को एंजॉय करते हुए मेंटल स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सकते हैं।

गोवा रहेगा बेस्ट

स्लीप टूरिज्म में आपको आयुर्वेदिक मालिश, योग और नींद लेने में सहायता की जाती है। ऐसे में स्लीप टूरिज्म के लिए गोवा बेस्ट लोकेशन है। समुद्र के किनारे बसी इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता आपको दीवाना बना देगी। आप समुद्र के किनारे रेत पर नींद लेकर खुद को प्रकृति के बेहद करीब देखकर आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे।

जानिए क्या होता है स्लीप टूरिज्म

आजकल स्लीप टूरिज्म काफी ज्यादा चलन में है। ऐसे में आप इन खूबसूरत जगहों पर जाकर नेचर के बीच अच्छी नींद ले सकते हैं। भागदौड़ भरी लाइफ से दूर अपने आप को समय देने और खुद को रिचार्ज करने को स्लीप टूरिज्म कहा जाता है। नींद एकमात्र ऐसा तरीका होता है, जो हमारे दिमाग को शांतकर मेंटल हेल्थ को दुरुस्त करता है। इस यात्रा के बाद आपको थकान दूर करने के लिए छुट्टी लेने या रेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है।

हिमाचल प्रदेश

बता दें कि टूरिज्म का यह तरीका तनाव को बेहतर तरीके से कम करने में सहायता करता है। आप हिमाचल प्रदेश की ठंडी हवा और खूबसूरत पहाड़ों के बीच घूमने का प्लान कर सकते हैं। यह जगह आपको शांति और सुकून देंगे। यहां पर आप योग, ट्रेकिंग और मछली पकड़ने वाली एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। हिमाचल की खूबसूरती को देखने के लिए आपको मनाली, कुल्लू और शिमला जाना चाहिए।

प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत स्थल है पंचगणी

पंचगणी, महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन है। यह स्थान अपने अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों, ठंडी जलवायु और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। पंचगणी का नाम यहाँ की पाँच पहाड़ियों के नाम पर रखा गया है, जो इसे एक अनोखी छटा प्रदान करते हैं। पंचगणी का इतिहास ब्रिटिश शासन के समय का है। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने गर्मियों में ठहरने के लिए कई बंगले और रिसॉर्ट्स बनवाए। आज भी यहाँ पर कई ब्रिटिश काल के भवन और बाग़ देखे जा सकते हैं, जो उस समय की स्थापत्य कला को दर्शाते हैं।

खंडाला और नदियों का संगम

पंचगणी के निकट स्थित कई नदियाँ और झरने इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ पर ट्रेकिंग और कैंपिंग का आनंद भी लिया जा सकता है।

पंचगणी का स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल

हर साल यहाँ स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जिसमें स्थानीय उत्पादकों द्वारा ताजे स्ट्रॉबेरी के विभिन्न व्यंजन प्रस्तुत किए जाते हैं।

संस्कृति और स्थानीय जीवन

पंचगणी की संस्कृति में स्थानीय महाराष्ट्रीयन परंपराएँ झलकती हैं। यहाँ के निवासी अपने मेहमानों का स्वागत करने में बहुत गर्मजोशी रखते हैं। स्थानीय बाजारों में आपको हस्तशिल्प, कला और शिल्प के अनूठे नमूने मिलेंगे।

यात्रा का सबसे अच्छा समय

पंचगणी जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी तक है, जब मौसम ठंडा और होता है। इस दौरान आप यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। पंचगणी एक ऐसा स्थल है जहाँ आप प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं और शांति की खोज में समय बिता सकते हैं। चाहे आप एक साहसी यात्री हों या एक शांति प्रेमी, पंचगणी आपके लिए एक आदर्श गंतव्य है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

प्रियंका के खिलाफ भाजपा की नव्या हरिदास ने किया नामांकन

वायनाड। वायनाड लोकसभा उपचुनाव से भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास ने अन्य भाजपा नेताओं के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार हरिदास ने आरोप लगाया कि लोगों को शूटिंग या वायनाड के पर्यटन स्थलों की सैर कराने के बहाने वहां लाया गया था और इसी वजह से रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। उन्होंने आगे कहा कि प्रियंका का आगमन और रोड शो एक मौसमी त्यौहार की तरह था जो हर साल केवल एक बार आता है। गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाली भाजपा उम्मीदवार ने कहा, लेकिन, लोग इसे समझ जाएंगे। हरिदास ने बुधवार को नामांकन दाखिल करने वाली प्रियंका पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस महासचिव केवल अपने प्रमुख राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर एक बड़ी उम्मीदवार हैं।

गांडेय सीट से कल्पना सोरेन ने भरा पर्चा

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने गुरुवार को गांडेय विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। कल्पना सोरेन वर्तमान में गांडेय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने इस साल मई में हुए उपचुनाव में भाजपा के दिलीप कुमार वर्मा को 27,149 मतों के अंतर से हराकर यह सीट जीती थी। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी। सूची के अनुसार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अन्य उम्मीदवारों में राजमहल सीट से एमटी राजा, बोरियो से धनंजय सोरेन, दुमका से बसंत सोरेन, मधुपुर से हफीजुल हसन, दमुरी से बेबी देवी, लातेहार से बैधनाथ राम और जमुआ सीट से केदार हाजरा शामिल हैं। इस बीच, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर बातचीत पूरी हो गई है और गतिरोध सुलझ गया है।

उत्तरप्रदेश में नहीं बनी सपा और कांग्रेस की बात?

लखनऊ। इंडिया ब्लॉक के सहयोगी समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रहा सस्पेंस बुधवार देर रात उस समय सुलझ गया, जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए घोषणा की कि पार्टी के उम्मीदवार आगामी उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सभी नौ विधानसभा सीटों पर सपा के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ेंगे। इस घोषणा से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि इंडिया ब्लॉक के सहयोगी सीट बंटवारे पर आम सहमति बनाने में विफल रहे हैं। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि 'बात सीट की नहीं जीत की है' इस रणनीति के तहत 'इंडिया गठबंधन' के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह 'साइकिल' के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर, कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है।

उद्धव ठाकरे परिवार के एक और सदस्य की चुनावी मैदान में एंट्री

मुंबई। वांद्रा ईस्ट विधानसभा सीट पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के भतीजे वरुण सरदेसाई के बीच मुकाबला होने की संभावना है। सरदेसाई के नाम की घोषणा शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल परब ने की। हालांकि, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के सहयोगियों ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि इस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा; कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) दोनों ने इस पर दावा किया है। परब ने बुधवार शाम बूथ स्तर पर काम करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में घोषणा की। उन्होंने कहा कि उद्धवजी ने वंद्रा ईस्ट से वरुण सरदेसाई को उम्मीदवार के रूप में अंतिम रूप दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि वह इस चुनाव में जीतेंगे। परब की घोषणा के बाद, मंच पर बैठे सरदेसाई ने खड़े होकर सभी का अभिवादन किया। सरदेसाई, जो रश्मि ठाकरे की बहन के बेटे हैं, चुनावी मैदान में उतरने वाले ठाकरे परिवार के दूसरे सदस्य हैं।

यूपी उपचुनाव के लिए भाजपा ने 7 प्रत्याशी की घोषणा की

लखनऊ। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी तक दी। उत्तर प्रदेश की नौ विधानसभा सीटों पर आगामी 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। भाजपा ने 7 प्रत्याशी की घोषणा की। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटेहरी से धर्मराज निषाद और मझवां से सुचिश्मिता मौर्या को टिकट दिया गया है। राजस्थान के लिए एक सीट की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उत्तर प्रदेश की नौ सीटों पर होने वाल उपचुनाव के मद्देनजर बृहस्पतिवार को सात उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने करहल से समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव के खिलाफ अनुजेश यादव को उतारा है। पार्टी ने मीरापुर (मुजफ्फरनगर) और सीसामऊ (कानपुर शहर) से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है।

महा विकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच हो सकती है सीट की अदला-बदली : संजय राउत

मुंबई। शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को संकेत दिया कि महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के सहयोगी दल आपस में कुछ सीट की अदला-बदली कर सकते हैं। राउत ने यह बात महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन एमवीए द्वारा तीनों घटक दलों को 85-85 सीट दिये जाने के फार्मूले की घोषणा के एक दिन बाद कही। उन्होंने यह भी कहा कि बुधवार को उनकी पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों की सूची में 'कुछ सुधार' हो सकते हैं।

कई दिनों के गतिरोध के बाद कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) और शिवसेना (यूबीटी) से मिलकर बने महा विकास आघाड़ी (एमवीए) ने बुधवार को 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए 85-85 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की, जबकि अंतिम समझौते पर मुहर लगाने के लिए विचार-विमर्श अभी भी जारी है। तीनों सहयोगी दल शेष 33 सीट आपस में तथा छोटे दलों के बीच बांटने पर चर्चा कर रहे हैं।

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) ने बुधवार को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 65 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। राउत ने गुरुवार को कहा, 'सीट की अदला-बदली हो सकती है।'

उन्होंने कहा कि उम्मीदवार चुनने में योग्यता और जीतने की संभावना मुख्य कारक होंगे। राउत ने कहा, 'एक या दो स्थानों पर सीट की अदला-बदली हो सकती है। कुछ स्थानों पर उम्मीदवारों को अंतिम समय में बदलना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि इससे आगे कुछ बड़ा हो सकता है।'

तीनों दल 85-85-85 (फॉर्मूले) पर सहमत हो गए हैं। राउत ने कहा कि शेष सीट पर निर्णय बृहस्पतिवार शाम तक लिया जाएगा। राज्यसभा सदस्य राउत ने यह भी संकेत दिया कि उनकी पार्टी 100 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। राउत ने क्रिकेट मैच के साथ तुलना करते हुए कहा, 'हम शतक बनाने के करीब पहुंच गए हैं। हम दो-तीन छक्के लगाएंगे। हमने 85 रन बनाए हैं और मैच अभी भी जारी है। हम शेष रन बना लेंगे।' राज्य विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होंगे और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी।

आज सुबह होगी एमवीए में सीट बंटवारे पर अंतिम घोषणा : नाना पटोले

इस बीच, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने बताया कि महा विकास अघाड़ी में सीट बंटवारे की अंतिम घोषणा शुक्रवार सुबह की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पहले ही उन उम्मीदवारों से नामांकन पत्र भरने के लिए कह दिया है, जिनका विधानसभा चुनाव के लिए टिकट हासिल करना तय है। पटोले ने पत्रकारों से कहा, अंतिम सीट बंटवारे की घोषणा आज शाम या कल सुबह होगी।पटोले से जब पूछा गया कि कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें पार्टी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा पहला काम एमवीए को सत्ता में लाना है। उन्होंने आगे कहा, मुख्यमंत्री के पद पर फैसला हाई कमान द्वारा लिया जाएगा।

दलितों के मुद्दे पर भाजपा का कांग्रेस पर आरोप

प्रियंका के नामांकन के दौरान खरगे को कमरे से निकाला

नई दिल्ली। प्रियंका गांधी ने बुधवार को केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा पर पलटवार किया है और इस मुद्दे को भाजपा की साजिश करार दिया। दरअसल भाजपा ने अपने सोशल मीडिया पर हैंडल पर एक वीडियो जारी की है। जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कमरे के बाहर इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं।

इस वीडियो के कैप्शन में भाजपा ने लिखा कि बुधवार को जिस तरह से मल्लिकार्जुन खरगे को प्रियंका वाड्रा के नामांकन के समय कमरे से बाहर रखा गया, ठीक उसी तरह राहुल गांधी आरक्षण हटाने के बाद दलित समाज के लोगों को सम्मान और अवसरों से वंचित रखेंगे। अगर गांधी परिवार खरगे जी को ऐसे अपमानित कर सकता है तो दलित समाज के प्रति इनके मन में कितनी घृणा होगी, ये समझा जा सकता है। भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने भी इसे लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने दलितों की कांग्रेस में स्थिति दिखाई है। बाहर से राहुल गांधी दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी दलितों का समर्थन करती है और उन्हें बराबर के अधिकार देती है, लेकिन अंदर से दलितों का अपमान किया जाता है। मल्लिकार्जुन खरगे के साथ जो हुआ, उसके बाद कहने के लिए कुछ नहीं रह गया है। कांग्रेस बेनकाब हो गई है। कांग्रेस पार्टी में दलितों का अपमान किया जाता है और उन्हें तीसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है और छुआछूत भी की जाती है।

भाजपा छोड़ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए नीलेश राणे

मुंबई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे महत्वपूर्ण राज्य विधानसभा चुनाव 2024 से पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब राणे के पिता ने चुनावों से पहले अपने बेटे को शिंदे की शिवसेना में शामिल कराने के लिए अथक प्रयास किए थे। उन्होंने नीलेश के लिए टिकट पर चर्चा करने के लिए रविवार को शिंदे से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने सीएम से अपने बेटे को कुडाल विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने का आग्रह किया है। नारायण ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी फोन किया। कुडाल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वर्तमान में शिवसेना (यूबीटी) विधायक वैभव नाइक करते हैं। नारायण, जिन्होंने 2019 में अपनी पार्टी - महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष का भाजपा में विलय कर दिया था, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने बेटे के लिए टिकट सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयास सफल हुए क्योंकि उनके बेटे को सत्तारूढ़ शिवसेना में प्रवेश मिल गया। 2019 में अविभाजित शिवसेना ने सिंधुदुर्ग जिले से कुडल और सावंतवाड़ी में जीत हासिल की, जबकि राणे के छोटे बेटे नितेश राणे ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में कंकावली से जीत हासिल की। 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद जब शिंदे बहुमत वाले विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी से बाहर चले गए, तो सावंतवाड़ी के विधायक दीपक केसरकर ने उनका साथ दिया।

इंडिया ब्लॉक के लिए महाराष्ट्र और झारखंड में प्रचार करेंगे केजरीवाल

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया ब्लॉक उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। सूत्रों के अनुसार अरविंद केजरीवाल उन विधानसभा सीटों पर प्रचार कर सकते हैं, जहां आप के पास स्वयंसेवक आधार है और जहां एमवीए उम्मीदवारों की कोई विवादास्पद पृष्ठभूमि नहीं है। सूत्र ने बताया कि शिवसेना-यूबीटी और एनसीपी-एसपी ने अरविंद केजरीवाल को महाराष्ट्र में प्रचार करने के लिए आम आदमी पार्टी से संपर्क किया है। केजरीवाल उन विधानसभा सीटों पर प्रचार कर सकते

हैं, जहां आप के पास स्वयंसेवक आधार है और जहां एमवीए उम्मीदवारों की कोई विवादास्पद पृष्ठभूमि नहीं है।

केजरीवाल के अलावा आप के अन्य वरिष्ठ नेता भी एमवीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। केजरीवाल झारखंड में जेएमएम उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल उन सीटों पर प्रचार करेंगे, जहां उनकी अपील इंडिया ब्लॉक के लिए वोटों में तब्दील होगी, खासकर शहरी सीटों पर। दिल्ली आबकारी नीति मामले में इस साल मार्च में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए केजरीवाल पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। बाहर आने के बाद, एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए, आप के राष्ट्रीय संयोजक ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की और कहा कि जब तक जनता उन्हें अगले साल विधानसभा चुनावों में आप को फिर से विजयी बनाकर ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं दे देती, तब तक वह पद नहीं लेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं, जबकि सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्य चुनावी मुकाबला दो गठबंधनों के बीच होगा, महायुति - जिसमें भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) और शिव सेना (एकनाथ शिंदे) शामिल हैं। दूसरा गठबंधन एमवीए है - जिसमें कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरद पवार) शामिल हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

द. अफ्रीका ने लगाई डब्ल्यूटीसी फाइनल की रेस में लंबी छलांग

मीरपुर। दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश में पहला टेस्ट मैच जीतकर डब्ल्यूटीसी फाइनल की रेस में लंबी छलांग लगाई है। अफ्रीकी टीम ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 3 विकेट से हराया। मेजबान बांग्लादेश ने मेहमान टीम को जीत के लिए 106 रन का लक्ष्य दिया था, जो दक्षिण अफ्रीका ने आसानी से हासिल कर लिया। इसके साथ ही उसने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच मीरपुर में खेला गया। दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को पहली पारी में 106 रन समेटा। इसके बाद उसने अपनी पहली पारी में 308 रन बनाए। इस तह उसे 202 रन की लीड मिली। बांग्लादेश ने इसके बाद दूसरी पारी में सुधरा प्रदर्शन किया। उसने मेहदी हसन मिराज (97) की बदौलत दूसरी पारी में 307 रन बना, लेकिन ये ऐसा स्कोर नहीं था कि दक्षिण अफ्रीका को तंग किया जा सके। दक्षिण अफ्रीका का एशियाई देशों में चौथी पारी में बैटिंग का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। उसकी छवि भी चोकर्स की रही है। ऐसे में बांग्लादेश के फैंस उम्मीद कर रहे थे कि उनकी टीम शायद कोई कमाल करे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने इस बार उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ये सिर्फ तीसरा मौका है जब दक्षिण अफ्रीका ने एशियन पिचों पर 100 रन से बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। उसने इससे पहले 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ ही मीरपुर में 205 रन का लक्ष्य हासिल किया था। दक्षिण अफ्रीका की टीम को इस जीत से 12 अंक का फायदा हुआ है। अब डब्ल्यूटीसी पॉइंट टेबल में 40 अंक और 47.62 विनिंग परसेंट हैं। अब वह पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर है। दक्षिण अफ्रीका इस मैच से पहले 38.89 विनिंग परसेंट के साथ छठे नंबर पर था। अफ्रीकी टीम ने इस जीत के बाद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

लगातार चौथे दिन लाल निशान में सेंसेक्स-निफ्टी

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार आज भी निवेशकों के लिए खास नहीं रहा। बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और एनएसई का निफ्टी-50 लगातार चौथे दिन लाल निशान में बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में सुस्ती के पीछे की वजह मुख्य रूप से पश्चिमी एशियाई देशों में तनाव, एफपीआई की तरफ से जमकर शेयरों की बिकवाली, चीन से सस्ते इंट्रेस्ट पर लोन और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच बढ़ती कांटे की टक्कर मानी जा रही है। 24 अक्टूबर को सेंसेक्स 0.02% या 16.82 अंक गिरकर 80,065.16 के लेवल पर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी-50 0.15% या 36.10 अंक गिरकर 24,399.40 के लेवल पर क्लोज हुआ। हालांकि, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के बड़ी गिरावट को रोकने में कामयाबी हासिल की। सेक्टोरल इंडेक्स की बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा, 1.22% का उछाल निफ्टी पीएसयू बैंक में देखने को मिला।

कटारिया इंडस्ट्रीज ने रतलाम वायर्स के तार विनिर्माण कारोबार का किया अधिग्रहण

नईदिल्ली। स्टील वायर बनाने वाली कंपनी कटारिया इंडस्ट्रीज ने रतलाम वायर्स के तार विनिर्माण कारोबार का करीब 31 करोड़ रुपये में अधिग्रहण करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। कंपनी ने बयान में कहा, इस अधिग्रहण से स्टील वायर क्षेत्र में उसकी स्थिति मजबूत होगी। रतलाम वायर्स स्टील वायर उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाती है, जिसमें स्प्रिंग स्टील वायर, पीसी स्ट्रैंड वायर, गैल्वनाइज्ड तथा अनगैल्वनाइज्ड वायर शामिल हैं। इसमें कहा गया, कटारिया इंडस्ट्रीज ने रतलाम वायर्स के वायर विनिर्माण प्रभाग का 30.6 करोड़ रुपये में अधिग्रहण किया है। कटारिया इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक ने कहा, इस अधिग्रहण से दोनों व्यवसायों के संयुक्त रूप से काम करने से हमारे 'टर्नओवर' तथा मुनाफे में वृद्धि होने की उम्मीद है।

अशोक लेलैंड को 500 इलेक्ट्रिक बसों का कॉन्ट्रैक्ट मिला

नईदिल्ली। वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता कंपनी अशोक लेलैंड की इकाई ओएचएम ग्लोबल मोबिलिटी को चेन्नई स्थित मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से 12 मीटर लंबी 500 अल्ट्रा-लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों का ठेका मिला है। कंपनी बयान के अनुसार, मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से मिले ठेके के अनुसार अशोक लेलैंड की एक अन्य अनुषंगी कंपनी स्विच मोबिलिटी, ओएचएम को स्विच ईआईवी12 मॉडल बसों की आपूर्ति करेगी। इनमें से 400 बसें गैर-वातानुकूलित होंगी, जबकि 100 बसें वातानुकूलित होंगी। ओएचएम अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक परिवहन शाखा है, जो 'मोबिलिटी-एज-ए-सर्विस' व्यवसाय पर केंद्रित है। अशोक लेलैंड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) शेनू अग्रवाल ने कहा, हम इलेक्ट्रिक परिवहन की ओर बढ़ने को प्रतिबद्ध हैं। एमटीसी के साथ यह साझेदारी स्वच्छ एवं अधिक कुशल परिवहन प्रणाली बनाने की दिशा में एक कदम है।

पीरामल फार्मा का दूसरी तिमाही में मुनाफा चार गुना होकर 23 करोड़ रुपये

नईदिल्ली। पीरामल फार्मा का चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ चार गुना होकर 23 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का गत वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में मुनाफा पांच करोड़ रुपये रहा था। पीरामल फार्मा ने बयान में कहा, दूसरी तिमाही में परिचालन आय बढ़कर 2,242 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 1,911 करोड़ रुपये थी। वहीं पीरामल फार्मा की चेयरपर्सन नंदिनी पीरामल ने बताया कि इस वृद्धि गति को बनाए रखने और 'स्टेराइल फिल-फिनिश' क्षमताओं की बढ़ती मांग को भुनाने के लिए कंपनी ने 'लेक्सिंगटन' सुविधा में आठ करोड़ डॉलर की विस्तार योजना की घोषणा की है, जिसके वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की जरूरत

डॉ. पीएस वोहरा

कुछ समय पहले विश्व बैंक ने भारत को चेताया है कि उसे अमेरिका की वर्तमान प्रति व्यक्ति आय के एक-चौथाई स्तर तक पहुंचने में अभी 75 वर्ष का समय और लग सकता है। उसने यह भी रेखांकित किया है कि मध्यम वर्गीय प्रति व्यक्ति आय के जाल में फंसना भारत के लिए बहुत संभव होता दिख रहा है। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति आय 2,500 डॉलर है और इसे 20,000 डॉलर तक पहुंचने में 2047 की विकसित भारत बनने की समय सीमा से भी अधिक समय लग सकता है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की चुनौतियां भविष्य में और गंभीर हो सकती हैं। वैश्विक मानकों के अंतर्गत उच्च मध्यवर्गीय आय की आर्थिक सीमा 13,845 डॉलर तक है। विश्व बैंक ने यह भी बताया है कि 1990 से लेकर अब तक वैश्विक स्तर पर मात्र 34 देश ही मध्यम वर्गीय आय से उच्च स्तर की प्रति व्यक्ति आय के दायरे में पहुंच पाये हैं। वे 34 मुल्क, मात्र 25 करोड़ के लगभग जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भारत की वर्तमान आबादी के 20 प्रतिशत से भी कम है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की तरक्की और उसकी चुनौतियों पर हो रही चर्चाओं के बाद से आर्थिक विस्तार एवं प्रगति को देखने-समझने का नजरिया बदलने लगा है। यह सवाल पूछा जा रहा है कि जीडीपी में निरंतर बढ़ोतरी का बहुत अधिक महत्व क्यों है। वर्तमान में सर्वाधिक जीडीपी वाले शीर्ष के 10 देशों में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भारत की है। इस समय भारत 3.94 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में अक्सर इसकी विशाल जनसंख्या का एक विपरीत

संदर्भ सदैव रहता है, पर सवाल उठता है कि चीन की अधिक आबादी का क्या। आर्थिक विकास के मोर्चे पर जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में चीन ने भारत को करीब डेढ़ दशक पहले ही पीछे छोड़ दिया था। यकीनन भारत ने पिछले तीन-चार दशकों में आर्थिक विकास का एक सुखद सफर तय किया है और जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। साठ से नब्बे के तीन दशकों तक भारत में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी दो गुना से कम ही दर्ज हुई, जबकि आर्थिक सुधारों के बाद से अब तक इसमें करीब पांच गुना बढ़ोतरी हुई है। लेकिन विश्व बैंक के अनुसार भारत को अब आमूलचूल परिवर्तन करने ही पड़ेंगे, अन्यथा अधिकांश आबादी का मध्य आय के जाल में फंसे रहना निश्चित है। पिछले 15 वर्षों से भारत की विकास दर पांच प्रतिशत या उससे अधिक रही है, पर इसी मामले में कुछ अन्य देशों, जिनमें कोरिया मुख्य उदाहरण के तौर पर सामने आता है, ने पिछले 50 वर्षों से अपनी विकास दर को बरकरार रखा है। भारत के पास अभी आगामी 20 से 25 वर्षों तक के लिए एक चुनौती है कि वह अपनी न्यूनतम विकास दर को पांच प्रतिशत या उससे अधिक बनाये रखे।

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुई प्रगति तथा भारतीयों के व्यक्तिगत आर्थिक जीवन स्तर में हुई वृद्धि ऐसे दो मुख्य आयाम है, जिनके बीच में एक तार्किक संबंध को स्थापित करना आवश्यक है। पिछले तीन दशक से दोनों में एक सकारात्मक संबंध भारतीय समाज में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, 2000 के दशक में पांच हजार रुपये प्रतिमाह वेतन पाने वाले व्यक्ति के लिए तब उपलब्ध न्यूनतम लागत की कार को खरीदने की क्रय क्षमता तीन से पांच वर्ष तक होती थी, जो आज छह माह पर आ गयी है क्योंकि अब वेतन 60 हजार रुपये प्रतिमाह के बराबर है। यह तथ्य एक विचित्र स्थिति को प्रस्तुत करता है कि आज भी भारत के विनिर्माण क्षेत्र द्वारा उत्पादित रेडीमेड कपड़ों को खरीदने की पहुंच आबादी के 20 प्रतिशत लोगों तक ही है क्योंकि उसकी लागत तीन हजार रुपये या उससे अधिक है। वहीं समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो 300 से 500 रुपये तक की कमीज या पतलून पहनता है, जिसे भारत बांग्लादेश व वियतनाम जैसे देशों से खरीदता है।

छत्तीसगढ़ शासन
सत्यमेव जयते

माता शबरी की भक्ति और
भगवान राम के आदर्शों से पावन,
माँ कौशल्या की धरा छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है

25-26 अक्टूबर

श्रीमती द्रौपदी मुर्मु
भारत की माननीय राष्ट्रपति
के करकमलों से महतारी वंदन योजना की
9वीं क़िस्त का अंतरण

प्रदेश की 70 लाख महिलाओं
को दीपावली से पहले
खुशियों का नोटिफिकेशन

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

संवाद- 41925/132

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.